● bordernewsmirror@gmail.com
● पटना, दिल्ली व कोलकाता से एक साथ प्रसारित
● द्विभाषिक समाचार पत्र

BORDER NEWS MIRROR BNM to the point...

02 तेजस्वी के सीट शेयरिंग फॉर्मूला से कांग्रेस को झटका
03 शिवहर में कमल के कार्यकर्ताओ मे मायूसी!

बॉर्डर न्यूज मिरर

...खबरों से समझौता नहीं

● पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024 | www.bordernewsmirror.com | ● पृष्ठ: 08, मूल्य: 5 रुपए ● वर्ष: 05, अंक: 16

सुधा मूर्ति ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

नयी दिल्ली। हाल ही में उच्च सदन के लिए मनोनीत की गई सामाजिक कार्यकर्ता ,इंजीनियर और जानीमानी लेखिका सुधा मूर्ति ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रीमती मूर्ति को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नेता सदन पीयूष गोयल, राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी और अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आठ मार्च को महिला दिवस के मौके पर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था।

नीतीश और राबड़ी समेत 11 प्रत्याशी निर्वाचित

पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 11 प्रत्याशी आज निर्विरोध चुन लिए गए। विधानसभा सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर राज कुमार ने गुरुवार को नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद सभी 11 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपा। श्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद संजय झा, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और कई अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से विधानसभा सचिव से मिले और प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। श्री नीतीश कुमार और श्रीमती राबड़ी देवी के अलावा निर्विरोध चुने जाने वालों प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंगल पांडे, अनामिका सिंह पटेल और लाल मोहन गुप्ता, जदयू के खालिद अनवर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संतोष मांझी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) की शशि यादव शामिल हैं।

महालक्ष्मी योजना महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी : राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए देने के ऐलान को क्रांतिकारी पहल करार देते हुए कहा है कि इसमें महालक्ष्मी योजना की घोषणा कर देश की महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और समृद्धि की गारंटी सुनिश्चित की गई है। श्री गांधी ने आज ट्वीट कर कहा , "महालक्ष्मी सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि आधी आबादी के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की गारंटी है। देश की हर गरीब महिला को 'महालक्ष्मी योजना' बहुत ध्यान से समझने की ज़रुरत है।"

उन्होंने कहा "कांग्रेस ने हर गरीब परिवार की एक महिला को महालक्ष्मी मान कर उनके खाते में साल के 1 लाख रुपए डालने का संकल्प लिया है। महिलाएं 'घर का बैंक' होती हैं जिनके पास गया एक-एक रुपया परिवार को मज़बूत बनाने में ही लगता है और मज़बूत परिवार ही मज़बूत समाज का आधार हैं।"

श्री गांधी ने कहा "महिला को अब किसी के आगे हाथ फैलाने या नज़र झुकाने की ज़रुरत नहीं होगी। पढ़ाई, कमाई और दवाई का बोझ घर की महिला खुद अपने कंधों पर उठाने में सक्षम होगी। महिलाओं के हाथ में एक लाख का मतलब परिवार के सामने अचानक आयी किसी विपदा से निपटने का इंश्योरेंस भी है।"

उन्होंने गरीब घरों की महिलाओं ध्यान में रखते हुए बनाई गई इस योजना को ऐतिहासिक करार दिया और कहा "यह योजना बड़ी संख्या में छोटे निवेश वाले बिजनेस शुरू करने में सहायक बन कर गांव-गांव महिलाओं को उद्यमी भी बनाएगी। कांग्रेस देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महिलाओं की आकांक्षाओं में निवेश पर विश्वास रखती है। संघर्ष के दिन खत्म हुए, अब खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं।"

राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में दी 3300 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी : गडकरी

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान, कर्नाटक तथा तेलंगाना में 3300 करोड रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस तरह की पहल से आर्थिक विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होती है। इसके अतिरिक्त, यह पर्यटन विकास को बढ़ावा देने और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करके रोजगार के भी अवसर पैदा करता है।

सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार बने चुनाव आयुक्त

नयी दिल्ली। ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना गुरुवार शाम जारी कर दी गयी।

विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इससे पहले इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 49) की खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कुमार, आईएएस (सेवानिवृत) और डॉ संधू, आईएएस (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में करने को मंजूरी प्रदान की। उनका कार्यकाल चुनाव आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से माना जायेगा।

इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयोग में खाली चुनाव आयुक्तों के दो पदों के लिये प्रधानमंत्री निवास में एक बैठक हुई जिनमें दो नामों पर सहमति बनी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह एवं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हुये। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गये थे। बाकी दोनों आयुक्तों के पद खाली होने और लोकसभा चुनाव आसन्न होने के कारण दोनों पदों पर शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति करना आवश्यक हो गया था।

जेजेए ने की राज्यपाल से पत्रकार पेंशन योजना लागू करने की मांग

रांची। झारखंड राज्य के सेवानिवृत्त पत्रकारों के हित में झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 लागू करने की मांग को लेकर भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड राज्य इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से सेवानिवृत्त पत्रकारों की लंबे समय से लंबित मांग को देखते हुए, राज्य सरकार उन्हें पेंशन देने पर सहमत हुई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019 में 'झारखंड पत्रकार पेंशन योजना' को मंजूरी दे दी थी और राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार द्वारा नियमों और विनियमों का एक सेट अधिसूचित किया गया था। पिछले लगभग पांच वर्षो से झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 लटक गई है। जिससे सेवानिवृत्त पत्रकारों को अनकही वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है विशेष रूप से, पेंशन राज्य के अनुमोदित नियमों और विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त एक उचित अधिकार का मामला है जो झारखंड में सेवानिवृत्त पत्रकारों की सेवा को नियंत्रित करता है। ज्ञात हो कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा सहित देश भर के अन्य राज्यों में पेंशन योजना से पत्रकार लाभांवित हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, हम, अधोहस्ताक्षरी, आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया संबंधित अधिकारियों को झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 और इसके नियमों और विनियमों की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित फाइलों की जांच करने और सेवानिवृत्त पत्रकारों को पूर्वव्यापी रूप से जल्द से जल्द पेंशन देने का आदेश दें। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलने वालों में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद भारती, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन, वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रसाद, सतीश महतो एवं वरुण सिन्हा शामिल थे।

सियासत | सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया बड़ा आरोप

घुसपैठियों के लिए भारत में आना आसान: केजरीवाल

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि जो अवैध घुसपैठिए देश में आने से डरते थे लेकिन केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) कानून बनाकर उनको भारत में आने को वैध बना रही है।

श्री केजरीवाल ने आज कहा कि बुधवार को उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके यह समझाया कि कैसे सीएए देश के लिए बेहद खतरनाक है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपना बयान जारी किया है। श्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहा उन्होंने सीएए पर जो प्रश्न उठाए थे, केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने पूरे बयान में किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। श्री शाह ने उन्हें अनाप शनाप और भ्रष्ट बताने के लिए अलावा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और देश की सारी राज्य सरकारें अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इतनी भारी संख्या में लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहती है, उनको नौकरियां कहां से देंगे? हमारे देश में पहले से ही इतनी गरीबी है। लोगों के पास नौकरियां और घर नहीं है। तो फिर इन देशों से आने वालो लोगों को कहां बसाएंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और पाकिस्तान-बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग भारत आए थे। अब सीएए की वजह से जो विस्थापन होने वाला है, वह आजादी के दौरान हुए विस्थापन से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या तो भाजपा की सरकार के दौरान ही भारत में आए थे। सीएए कानून आने के बाद से अब देश में इतनी भारी संख्या में रोहिंग्या आने वाले हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे देश में 2014 के पहले भी इन देशों से लोग आए थे, अभी तक हमारे देश में उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। अब उनको भारत की नागरिकता देकर उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अब आपकी सरकार पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को सरकारी नौकरियां देगी।

भाजपा सहित 32 दल सभी चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में

नयी दिल्ली। एक देश, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने देश भर में त्रिस्तरीय सभी चुनाव एक साथ कराने के लिये दो-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। पहले कदम के रूप में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गयी है। समिति का कहना है कि दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जा सकता है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर हो जायें। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), दो राष्ट्रीय पार्टियों से 32 सहित लोक सभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले 46 राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन किया।

MADAN RAJ NURSING HOME
HOSPITAL ROAD MOTIHARI, (BIHAR)
Contact No.- 9801637890, 6200450565, 9113374254

तेजस्वी के सीट शेयरिंग फॉर्मूला से कांग्रेस को झटका

पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सभी लोग निश्चिंत दिख रहे हैं। उधर, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे बिहार की सीटों की घोषणा एनडीए से पहले करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरे में से एक हैं। उधर, कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं दे रही है। जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देगी, उतने पर ही सब्र करना होगा। ज्यादा ये हो सकता है कि सोनिया गांधी

का फोन आने के बाद लालू यादव एक दो सीट में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा होता कम दिख रहा है। जानकारों ने माना कि लालू यादव का विरोध करने की क्षमता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में भी नहीं है। क्योंकि उन्हें राज्यसभा लालू यादव की पार्टी ने ही भेजा है।

कांग्रेस के उड़े होश

तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक संख्या जानने के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस जहां बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। वैसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने काफी कम सीटों का ऑफर दिया है। संख्या को लेकर बिहार कांग्रेस में नाराजगी है। ध्यान रहे कि हाल में आरजेडी के सहयोग से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आरजेडी ने उसका भी बदला ले लिया और कांग्रेस के एक भी सदस्य को विधान परिषद में नहीं भेजा। कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती है। तेजस्वी यादव का फार्मूला ऐसा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें दी जा रही हैं। इन सात सीटों पर कांग्रेस को सब्र करना होगा। सूत्रों की मानें, तो तेजस्वी यादव के ऑफर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता नाराज हैं। आखिर में लालू यादव से बातचीत करने की बात सामने आ रही है।

एक देश–एक चुनाव कमेटी की अनुशंसा स्वागतयोग्य' सुशील मोदी

पटना। एक देश-एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को सौंप दिया है और देश में लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ निकाय चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इसे स्वागतयोग्य बताया है।

सुशील कुमार मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 'एक राष्ट्र, 'एक चुनाव' पर गठित समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौपें जाने का स्वागत किया है। जिसमें यह अनुशंसा की गई है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से अनुशंसा की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि देश में 1967 में अंतिम बार दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। वर्षभर

चुनाव होने से हमेशा आचार संहिता लगी रहती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सुरक्षा बलों को बार-बार प्रतिनियुक्ति करने पर तथा राजनीतिक दलों को भी काफी खर्च करना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है। 2019 के भाजपा के घोषणा पत्र में भी 'एक राष्ट्र, 'एक चुनाव' शामिल था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे अपने तीसरे कार्यकाल में 'एक राष्ट्र,'एक चुनाव' को लागू करने का काम करें।

'CAA का विरोध करने वालों के लिए एक ही सजा फांसी' पटना में विधायक आवास के बाहर लगे पोस्टर, बवाल

पटना। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर देश में माहौल गरम है। सीएए के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में विपक्षी दल राजद, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी विरोध जता रही हैं। इधर राजधानी पटना में गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन और विरोध करने वालों के खिलाफ पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर विधायक आवास के बाहर लगाया गया है। ऐसा लगता है ये पोस्टर उन विधायकों को ध्यान में रखकर लगाया गया है, जो सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। बताते चलें जहां पोस्टर लगा है, वहां लेफ्ट और आरजेडी विधायकों के भी आवास हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी इसी रास्ते से अपने आवास जाते हैं।

'CAA का विरोध करने वालों के लिए एक सजा- फांसी'

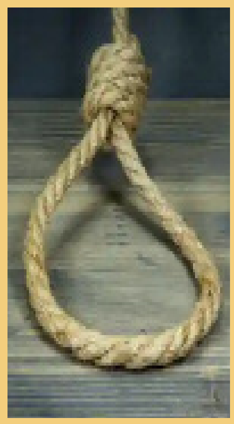

विधायकों की सरकारी आवास के ठीक बाहर लगाए गए इस पोस्ट में नागरिक संशोधन अधिनियम का समर्थन किया गया है। इस कानून का समर्थन करते हुए उन लोगों को गद्दार और देशद्रोही बताया गया है, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पोस्टर में इस कानून का विरोध करने वालों के लिए फांसी की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया है- 'देशद्रोही और गद्दारों के लिए एक ही सजा फांसी।'

राष्ट्रीय लोजपा में टूट के संकेत: चिराग पासवान से मिले पारस के सांसद

पटना। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एक और झटका देने की तैयारी कर ली गई है। पारस को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलने की चर्चा के बीच खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद महबूब अली कैसर ने बड़ा एलान कर दिया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में इस बार पारस का पत्ता साफ हो गया है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में पार्टी के सांसदों को अब अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और वे दूसरे विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली सांसद वीणा देवी आज अचानक चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने की ईच्छा जताई है। चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि उन्होंने चिराग पासवान से अपनी बात कह दी है और अगर चिराग उन्हें खगड़िया से टिकट देते हैं तो वे चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा है कि अगर लोजपा से टिकट नहीं मिलता है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। कैसर ने पारस का साथ छोड़ने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोजपा के तीन सांसदों में से एक वैशाली सांसद वीणा देवी पहले ही पारस का साथ छोड़ चुकी हैं और अब खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर चिराग उन्हें खगड़िया से टिकट देते हैं तो वे लोजपा (रामविलास) से चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

होली का त्योहार को लेकर बिहार पुलिस की छुट्टियां रद्द

पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। होली का त्योहार 25 मार्च को है, ऐसे में पुलिसकर्मियों की छुट्टी 20 मार्च से 28 मार्च तक रद्द की गयी है। गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार होली के मौके पर राज्य में विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया गया है। विशेष परिस्थिति के अवकाश को इससे अलग रखा गया है। इस पत्र को लेकर बिहार के डीजीपी की सहमति प्राप्त है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में बी-सैप के महानिदेशक, महानिदेश (प्रशिक्षण), अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, सीआईडी, विशेष शाखा, ईओयू एवं ऑपरेशन, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक को भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च होगा, नक्सल जिलों के लिए अलग से रणनीति वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जाएगा।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर घिरी सरकार जनता का ध्यान भटका रही : दीपंकर

पटना। सीएए के विरोध में भाकपा माले ने गुरुवार को विरोध दिवस मनाया। गुरुवार को राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना को राजनीतिक साजिश बताया है।

माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नफरत व विभाजन का माहौल बना रही है। यह ऐसा कानून है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए किसी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी उत्पीड़ति को तो नागरिकता प्रदान करता है लेकिन मुसलमानों को इससे अलग कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर घिरी भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजधानी पटना के अलावा गया, दरभंगा, सुपौल, नासरीगंज, बिहारशरीफ, पटना ग्रामीण के मसौढ़ी, दुल्हिनबाजार, नवादा, बेगूसराय आदि जगहों पर विरोध दिवस मनाया गया। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित प्रतिवाद सभा को माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, विधायक महबूब आलम और शिक्षाविद् गालिब ने संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन एआइपीएफ के कमलेश शर्मा ने किया। पार्टी नेता धीरेन्द्र झा, केडी यादव, अमर, ऐपवा महासचिव मीना तिवारी, स्कीम वर्कर आंदोलन की नेता शशि यादव, रसोइया आंदोलन की नेता सरोज चौबे, ऐक्टू नेता रणविजय कुमार आदि मौजूद रहे।

श्रम विभाग से जोड़ने को लेकर मनरेगा कर्मियों की हुई बैठक

रामगढ़वा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को श्रम विभाग से जोड़ने के लिए प्रखंड कार्यालय रामागढ़वा में रोजगार सेवकों को बैठक मनरेगा पीओ अमर्तेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में रामगढ़वा के प्रभारी

श्रम अधिकारी दिवाकर प्रसाद भी मौजूद रहे ।इस अवसर पर मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की पंचायतवार जानकारी ली गई ।और इनको श्रम विभाग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।मनरेगा पीओ से सभी रोजगार सेवकों से इनकी सूची शीघ्र हाड़ कापी में उपलब्ध करने का निर्देश दिया ।वही इस बैठक में उपास्थि श्रम अधिकारी ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का श्रम विभाग में कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करेगा जिसमे ट्राई साइकिल, साइकिल, व अन्य कई लाभ सामिल है।

M.S. MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
BALGANGA, ARERAJ ROAD, MOTIHARI
Contact No.- 9939047109, 9431203674

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विद्यालयों का किया निरीक्षण, दिया दिशा-निर्देश

बीएनएम@केसरिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रखण्ड क्षेत्र के तीन विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों में छात्र व शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय भवन की स्थिति, शौचालय, स्मार्ट क्लास, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित पंजी आदि की जानकारी ली।

उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया के निरीक्षण के क्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने प्रभारी एचएम संजीव रंजन को विद्यालय भवन के क्षतिग्रस्त खिड़की को अविलंब दुरुस्त कराने को कहा। वहीं विद्यालय में स्थापित आधार सेंटर के बारे में भी केंद्र संचालक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ हीं छात्र-छात्राओं का प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड बनाने को कहा। निदेशक श्री प्रसाद ने बीआरसी, मध्य विद्यालय केसरिया बालक, जय प्रभा प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसरिया आदि विद्यालयों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीईओ संजीव कुमार, बीईओ विनय कुमार तिवारी, बीपीएम अनिल कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

महात्मा गाँधी वस्त्र बैंक के द्वारा बच्चों के बीच वस्त्र का किया गया वितरण

बीएनएम@केसरिया। राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या में संचालित महात्मा गाँधी वस्त्र बैंक के द्वारा गुरुवार को विद्यालय के छात्र- छात्राओं के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। पोषक क्षेत्र के अभिभावकों ने विद्यालय के इस नवाचार पहल के लिए विद्यालय परिवार व वस्त्र बैंक के निदेशक की सराहना की है। विद्यालय के शिक्षक सह वस्त्र बैंक के निदेशक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि विद्यालय पोषक क्षेत्र के अध्ययनरत छात्र-छात्राएं वस्त्राभाव में न रहे, इसी उद्देश्य से महात्मा गाँधी वस्त्र बैंक की स्थापना की गई है। जिसमें शिक्षक, बच्चे, अभिभावक व समाजसेवियों द्वारा नये - पुराने वस्त्रों को जमा कराया जाता है।

इन वस्त्रों को जरुरतमंद बच्चों के बीच समय- समय पर वितरण किया जाता है।शिक्षक श्री सिंह ने बताया कि विद्यालय मात्र शिक्षादान का केन्द्र ही नहीं बल्कि जनसाधारण के बच्चों के लिए सर्वांगीण सहायता केन्द्र भी बने। ताकि आम बच्चे भी प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ सकें। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक वासुदेव राम, नवल पासवान, सुरेश कुमार, स्वामी चरण, चाँदनी कुमारी, रिया कुमारी, प्रियांशु कुमार, दीपांशु कुमार, सोनू कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

शिवहर में कमल के कार्यकर्ताओ मे मायूसी!

लवली आंनद हों सकती है जेडीयू से उम्मीदवार ?

मनोज कुमार

शिवहर। शिवहर लोकसभा की सीट को लेकर जिस तरह से सोसल और इलक्ट्रोनिक मिडिया में खबर आ रही है की शिवहर की सीट इस बार जेडीयू की खाते में जा सकती है और बाहुबली शिवहर के पूर्व सांसद आंनद मोहन की पत्नी शिवहर से उम्मीदवार हो सकती है। वैसे ही भाजपा के कार्यकताओं में मायूसी छाने लगी हैं।

साथ ही कल शाम सीएम नीतिश कुमार के साथ आंनद मोहन और लवली आंनद की फोटो आने के बाद इस चर्चा को काफ़ी बल मिला है। उसके बाद कमल यानि बीजेपी के कार्यकर्ता मे बैचेनी छा गई है। बकायदा कई कार्यकर्ता कल पटना पहुंच कर पार्टी कार्यालय में विरोध दर्ज करा चूके है। जबकि जेडीयू के कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहें है।

जेडीयू के जिला स्तरीय कार्यकर्ता और नेताओ का कहना है की अगर गठबंधन में जेडीयू को सीट मिल रहा है तो किसी को कोई परेशानी नही होनी चाहिए ।पिछले कई बार से जेडीयू के लोग बीजेपी के उम्मीदवार के तन मन से मदद कर जीतने का काम किया है। हालांकि, बीजेपी की रमा देवी तीन बार से इस सीट से चुनाव जीतते आ रही हैं इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा इसकी तो ओपचारिक अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी तक जदयू और बीजेपी में सीटों के बंटवारा ऐलान नहीं हुआ है।

मगर इस बार देखना होगा कि यह सीट बीजेपी या जदयू किसके पास होगी। बताया यह भी जाता है कि वर्तमान सांसद रमा देवी की टिकट कटने के स्थिति में बीजेपी की ओर से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे।

वहीं कुछ लोग दबे जुबान से भी कहते थे कि उन लोगों को पहले से ही आभास हो गया था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र के शिवहर से विधायक चेतन आनंद के विश्वास मत के दौरान जेडीयू के समर्थन करने के बाद से ही शिवहर की सीट जदयू की खाते में जाने की चर्चा होने लगी थी।

बहरहाल यह सीट बीजेपी को मिलती है या जदयू की कोटे में जाती है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद शिवहर लोकसभा क्षेत्र में काफी राजनीतिक गर्माहट हो गई है।

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए झड़प में 10 नामजद व 50 अज्ञात पर मामला दर्ज

मोतिहारी। जिले के रक्सौल शहर में नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों और नगरपरिषद कर्मियों से हुए झड़प को लेकर 10 नामजद व 50 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया। झड़प के दारान नगर परिषद के कई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।मामले को परिषद के ईओ अनुभूति श्रीवास्तव के निर्देश पर जेई राजकुमार के आवेदन पर 10 नामजद व 50 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा ने बताया कि जेई राजकुमार राय के आवेदन पर कांड संख्या 77/24 दर्ज किया गया है। जिसमें मौजे वॉर्ड नंबर 20 निवासी देवनाथ कुमार, कृष्णा दास, पोस्ट ऑफिस रोड़ निवासी मनोज कुमार, नूरसेद आलम, साहेब मियां, संतोष कुमार, फुल्लू मियां, इस्लामपुर निवासी कमसुदीन मियां, हनुमान कुमार सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

हथियार के साथ आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार

एक देशी कट्टा, चार बाइक, चार जिंदा कारतूस व तीन मोबाइल बरामद

बीएनएम@केसरिया

पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे छह अपराधियों को हथियार व लूट की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना में गुरुवार को प्रेस वार्ता में चकिया के पुलिस उपाधीक्षक सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात्रि सूचना मिली कि राजपुर कोठी चौक पर बड़ी संख्या में अपराधी एकत्रित होकर अपराध की योजना बना रहे हैं।

जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। जहाँ से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थानांतर्गत हिम्मतपट्टी निवासी भोला कुमार, गोलू कुमार, सुमन कुमार एवं केसरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के विकास कुमार, कटहरिया के यश सिंह व बनकट माफी के कुंदन कुमार को धर दबोचा गया। इन अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, चार बाइक व तीन मोबाइल बरामद की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से दो का आपराधिक इतिहास है। गोलू केसरिया थाना में दर्ज लूटकांड मामला में आरोपी है। वहीं विकास पर हत्या मामले में एफआईआर दर्ज है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों को आवश्यक पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में डीएसपी के अलावा केसरिया थानाध्यक्ष उदय कुमार, एसआई बादशाह चौहान, एसआई अरुण कुमार यादव, पीएसआई अंजू कुमारी, पीएसआई राजीव कुमार सहित पुलिस बल शामिल थे।

अगलगी की घटना में पिकअप समेत दर्जनों घर जलकर राख

बीएनएम@मोतिहारी

जिले के बनकटवा प्रखण्ड क्षेत्र के पकही गांव में अचानक हुई अगलगी की घटना में पिकअप समेत दर्जन भर घर जलकर राख हो गये। घटना गुरुवार की शाम की है।

सूचना पर मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की पांच गाड़ी व लखौरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुझाने में सहयोग किया। बताया गया कि आग शॉट सर्किट से लगी है। बनकटवा मुखिया प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवारो में सभाजीत राय, मटर राय, लालू राय, पंजाबी राय, बब्लू राय, प्रमोद राय, अनोज राय, संतोष राय, टोना राय, जगदीश राय तथा नितेश राय के घर जलकर राख हो गये है।

घटना में सभाजीत राय के भैंस के साथ उसका एक बच्चा तथा आधा दर्जन बकरियां

पूरी तरह से जल गये।साथ ही घटना में दरवाजे पर खड़ी एक पिकअप गाड़ी,चार बेरी धान ,कपड़े,आभूषण,घर मे रखे चावल दाल ,वर्तन सब जलकर राख हो गया।आग इतना भीषण था कि घर के बगल खेत मे लगे गेंहू फसल पूरी तरह से जल गये। वही सीओ अतुल कुमार बादल ने बताया कि घटना स्थल पर कर्मचारी को क्षति का जायजा लेने के लिए भेजा गया है।क्षति का आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अग्नि पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा उपलब्ध करायी जाएगी।

निर्वाचन के लिए चिन्हित डिस्पैच सेन्टर पर जरूरी तैयारी करायें : जिलाधिकारी

बीएनएम@मोतिहारी

लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 12 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर्मियों को मतदान केन्द्र के लिए डिस्पैच हेतु जिला में डिस्पैच सेन्टर चिन्हित कर लिया गया है। इसके अनुसार 10-रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नन्द +2 उच्च विद्यालय, सुगौली, 11 सुगौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नन्द +2 उच्च विद्यालय, सुगौली, 12-नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएस कॉलेज, मोतिहारी, 13- हरसिद्धि (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए महंत शिव शंकर गिरी कॉलेज अरेराज, 14-गोविन्दगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री सोमेश्वर नाथ+2 उच्च विद्यालय, अरेराज, 15-केसरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उच्च विद्यालय, केसरिया, 16-कल्याणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एसआरएपी कॉलेज बारा चकिया, 17 पिपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एसआरएपी कॉलेज बारा चकिया, 18- मधुबन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजकीय कृत जयमंगल उच्च विद्यालय चैता, पकड़ीदयाल, 19-मोतिहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएस कॉलेज मोतिहारी, 20- चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखण्ड सूचना केन्द्र चिरैया, 21-ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए महादेव साह+2 उच्च विद्यालय, चिरैया को डिस्पैच सेन्टर बनाया गया है।

मतदान कर्मियों के लिए डिस्पैच सेन्टर पर सभी जरूरी व्यवस्था करते हुए सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर्मियों का डिस्पैच कार्य सम्पन्न कराने के लिए सभी डिस्पैच सेन्टर का वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी रक्सौल को 10-रक्सौल के लिए प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मोतिहारी को 11- सुगौली के लिए, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रक्सौल को 12-नरकटिया के लिए, भूमि सुधार उप समाहर्ता अरेराज को 13- हरसिद्धि (अ०जा०) के लिए, अनुमण्डल पदाधिकरी, अरेराज को 14-गोविन्दगंज के लिए, उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को 15-केसरिया के लिए, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया को 16 कल्याणपुर के लिए, अनुमण्डल पदाधिकारी चकिया को 17 पिपरा के लिए, अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ीदयाल को 18 मधुबन के लिए, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर को 19- मोतिहारी के लिए, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिकरहना ढाका को 20 चिरैया के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी सिकरहना ढाका को 21-ढाका के लिए बनाये गये डिस्पैच सेन्टर का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है।

इन पदाधिकिारियों को डिस्पैच स्थल पर मतदान कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बैठने हेतु स्थान का निर्धारण, सामग्री एवं ईवीएम उपलब्ध कराने हेतु काउन्टर का निर्धारण, ईवीएम के कमिशनिंग एवं अस्थायी वज्र गृह स्थान का चिन्हिकरण एव ससमय ईवीएम कमिशनिंग कराने का दायित्व दिया गया है।

इसके अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग का चिन्हिकरण, मतदन कर्मियों का योगदान एवं पार्टी मिलान, मतदान सामग्री का वितरण, ईवीएम एवं वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भसी सौंपी गई है। जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया है कि सभी वरीय पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी डिस्पैच सेन्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ससमय तैयार करायेंगे।

पश्चिम चंपारण के मजदूर की तमिलनाडु में मौत

बेतिया। बेतिया पुलिस जिला स्थित गौनाहा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव के पुत्र मनु कुमार की मौत तमिलनाडु के विजयवाड़ा में 11 मार्च को संदिग्ध अवस्था में रात्रि करीब 11 बजे हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उसके हुए आकस्मिक मौत से पूरे परिवार मे दुखों का पहाड़ टूट गया है। उक्त युवक वहां मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार को एंबुलेंस से लाश को युवक के पैतृक गांव मझरिया लाया गया। हाल ही में उसकी शादी होने वाली थी। दो भाइयों में मनु छोटा भाई था। मृतक के पिता बालदेव चौधरी ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा लाश का पोस्टमार्टम करा कर बेतिया भेजा गया है।

पश्चिम चंपारण के मजदूर की तमिलनाडु में मौत

बेतिया। बेतिया पुलिस जिला स्थित गौनाहा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव के पुत्र मनु कुमार की मौत तमिलनाडु के विजयवाड़ा में 11 मार्च को संदिग्ध अवस्था में रात्रि करीब 11 बजे हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उसके हुए आकस्मिक मौत से पूरे परिवार मे दुखों का पहाड़ टूट गया है। उक्त युवक वहां मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार को एंबुलेंस से लाश को युवक के पैतृक गांव मझरिया लाया गया। दो भाइयों में मनु छोटा भाई था। मृतक के पिता बालदेव चौधरी ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा लाश का पोस्टमार्टम करा कर बेतिया भेजा गया है।

जेपी सेनानीयों ने की आवश्यक बैठक

मोतिहारी। भूमिहार ब्राह्मण छात्रावास के राय हरिशंकर शर्मा सभागार में जे पी सेनानीयों की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष राय सुन्दर देव शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिसमें आगामी 18 मार्च को बिहार में भ्रष्टाचार, महगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षानिति मे परिर्वतन के मांग को लेकर 18 मार्च 1974 को जिस आंदोलन की सुरूआत हुई थी और जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था जिसने देश के राजनीति का स्वरूप हीं बदल दिया था उसका 50 वां वर्षगांठ है जिसे उत्साहपूर्ण ठंग से मनाने के लिए 18 मार्च को मोतिहारी में जयप्रकाश जी को मानने एवं सभी जे पी सेनानी ऐकत्रित होगें एवं आन्दोलन के अधूरे सपने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में विनय कुमार वर्मा,अरुण कुमार सिन्हा, प्रो अखिलेश सिंह, भरथ गुप्ता,केशव प्रसाद, जयनारायण कुशवाहा, योगेन्द्र नाथ गिरी, शिवचंद्र दूबे, विजय जयसवाल, हरेंद्र प्रताप सिंह आदी मौजूद थे।

केविवि में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

मोतिहारी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से गुरूवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविधालय के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों को प्रतिष्ठित फेलोशिप के अवसर प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करना था। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों को समर्थन और प्रोत्साहन देते कहा कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित फेलोशिप अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों को बहुमूल्य जानकारी और मार्गदर्शन से लैस करना है, जिससे शैक्षणिक विकास और सहयोग को बढ़ावा मिले।

ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रतिष्ठित फ़ेलोशिप अवसरों तक पहुँचने के लिए संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों को बहुमूल्य जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को अकादमिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से लैस करना था।

यूएसआईईएफ कोलकाता के क्षेत्रीय अधिकारी सुमंत बसु ने विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न फेलोशिप कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी से लोगो को अवगत कराया। सुश्री सुप्रभा डे, पीएच.डी. शिक्षा विभाग, ने सभी उपस्थित लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। जबकि शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. आशीष श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का समापन आस्तिक मिश्रा, पीएच.डी. शिक्षा विभाग ने सभी प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त कर किया ।इस कार्यक्रम में सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक,शोधार्थी, छात्र, प्रशाशनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

हर दृष्टि से सेहत के लिए हानिकारक है धूम्रपान

धूम्रपान निषेध दिवस

राकेश अचल

धूम्रपान छोड़ने के फायदों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि धूम्रपान छोड़ने के सिर्फ बीस मिनट के अंदर उच्च रक्तचाप में गिरावट आती है तथा बारह घंटे के बाद रक्त में कार्बन मोनोक्साइड के विषैले कणों का स्तर सामान्य हो जाता है। दो से बारह सप्ताह में फेफड़ों की कार्यक्षमता में तेजी से वृद्धि होती है तथा एक से नौ माह में खांसी तथा श्वसन संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं।

धूम्रपान के आदी मित्रों और परिजनों को धूम्रपान छोड़ने के लिए मदद पाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जो इस वर्ष 13 मार्च को मनाया जा रहा है। यह दिवस पहली बार 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। प्रतिवर्ष यह दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है, जो इस साल 'तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा' विषय के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल यह गहन चिंतन का विषय है कि पिछले कई दशकों में दुनियाभर में हुए अनेक अध्ययनों में यह प्रमाणित हो चुका है कि धूम्रपान हर दृष्टि से सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन जब तमाम जानकारियों और तथ्यों के बावजूद हम अपने आसपास बच्चों को भी धूम्रपान करते देखते हैं तो स्थिति बेहद चिंताजनक प्रतीत होती है। ऐसे बच्चों के मनोमस्तिष्क में धूम्रपान को लेकर कुछ गलत धारणाएं विद्यमान होती हैं, जैसे धूम्रपान से उनके शरीर में चुस्ती-फुर्ती आती है, उनका मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है आदि-आदि। चूंकि बच्चों का मन कोमल होता है, इसीलिए तमाम वैज्ञानिक शोधों के बावजूद वे यह समझने की स्थिति में नहीं होते कि धूम्रपान करने से उनके अंदर ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं होने वाली कि देखते ही देखते वो किसी ऊंचे पर्वत पर छलांग लगा सकें या महाबली पवनपुत्र हनुमान की भांति विशाल समुद्र लांघ जाएं। वास्तविकता यही है कि धूम्रपान एक ऐसा धीमा जहर है, जो धीमे-धीमे इसका सेवन करने वाले व्यक्ति का दम घोंटता है और बच्चों पर तो इसका प्रभाव बहुत घातक होता है। धूम्रपान शरीर में कई प्रकार की प्राणघातक बीमारियों को जन्म देता है और ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया तक पहुंचा देने का माध्यम बनता है।

दुनियाभर में धूम्रपान के कारण हर साल 70 लाख से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में होने वाली मौतों में से हर 5 में से 1 पुरूष की मौत धूम्रपान के कारण हो रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार माना गया है कि विकसित देशों में चालीस फीसदी से ज्यादा पुरूष और इक्कीस फीसदी से ज्यादा स्त्रियां धूम्रपान करती हैं जबकि विकासशील देशों में सिर्फ आठ फीसदी स्त्रियों को इसकी लत लगी है तथा पुरूषों की संख्या पचास फीसदी से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तम्बाकू के सेवन के कारण प्रतिदिन करीब आठ हजार व्यक्ति फेफड़ों के कैंसर के शिकार होकर मर जाते हैं। संगठन का अनुमान है कि यदि दुनियाभर में धूम्रपान की लत ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत जल्द धूम्रपान के कारण पचास करोड़ लोग मारे जा चुके होंगे और अगले तीस वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूम्रपान से मरने वालों की संख्या दस लाख से बढ़कर सत्तर लाख तक पहुंच जाएगी। संगठन का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्वभर में आठ हजार से ज्यादा नवजात शिशु धूम्रपान की वजह से असमय काल के ग्रास बन जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में से करीब 40 फीसदी का कारण धूम्रपान ही होता है। तीन दशक पूर्व प्रकाशित अपनी पुरस्कृत पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि धूम्रपान वास्तव में एक ऐसा धीमा जहर है, जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे प्राणघातक रोगों को जन्म देता है और व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया पर पहुंचा देता है। धूम्रपान कितना खतरनाक है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सिगरेटों के खतरनाक धुएं से करीब 50 टन तांबा, 15 टन शीशा, 11 टन कैडमियम तथा कई अन्य खतरनाक रसायन वातावरण में घुलते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों में भी धूम्रपान काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धूम्रपान से बचना चाहिए।

अपनी पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि सिगरेट के धुएं में पोलिनियम 210, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड, निकल, पाईरीडिन, बेंजीपाइरीन, नाइट्रोजन आइसोप्रेनावाइड, अम्ल, क्षार, निकोटीन, टार, जिंक, हाइड्रोजन साइनाइड, कैडमियम, ग्लायकोलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, एसीटिक एसिड, फार्मिक एसिड, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि चार हजार से भी ज्यादा घातक रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं, जो मानव शरीर को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। गर्भवती महिलाओं द्वारा धूम्रपान किए जाने से कम लम्बाई और कम वजन के बच्चों का जन्म, बच्चों में अपंगता तथा बाल्यावस्था में ही घातक हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रतिदिन बीस सिगरेट तक पीने वाली गर्भवती महिला के बच्चे की मृत्यु होने की संभावना सामान्य के मुकाबले बीस फीसदी बढ़ जाती है जबकि बीस से अधिक सिगरेट पीने पर यह खतरा पैंतीस फीसदी तक हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक किसी दूसरे के धूम्रपान के धुएं के प्रभाव से दिल के दौरे से होने वाली मौतों की आशंका तीस फीसदी बढ़ जाती है।

बहरहाल, धूम्रपान छोड़ने के फायदों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि धूम्रपान छोड़ने के सिर्फ बीस मिनट के अंदर उच्च रक्तचाप में गिरावट आती है तथा बारह घंटे के बाद रक्त में कार्बन मोनोक्साइड के विषैले कणों का स्तर सामान्य हो जाता है। दो से बारह सप्ताह में फेफड़ों की कार्यक्षमता में तेजी से वृद्धि होती है तथा एक से नौ माह में खांसी तथा श्वसन संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मनुष्य के फेफड़ों में जादुई क्षमता होती है, जो धूम्रपान से होने वाले कुछ नुकसान को स्वयं ठीक कर देती है और जो व्यक्ति धूम्रपान छोड़ देते हैं, उनकी चालीस फीसदी कोशिकाएं ऐसे लोगों की तरह ही हो जाती हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया।

संपादकीय

बनी रहे चुनाव आयोग की गरिमा

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्त हो गए व अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुमरु ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब 15 मार्च तक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। कानून मंत्री के नेतृत्व में खोज समिति दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी। जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के लिए दो नाम तय करेंगे। इसमें एक केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गोयल के इस्तीफे के कारणों पर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस थे। वह 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि गोयल के कुमार के साथ रहे मतभेदों के कारण यह स्थिति जन्मी हो। मगर आंतरिक संचार व निर्णयों के रिकार्ड में गोयल की कोई असहमति नहीं नजर आयी है। इसलिए इसे व्यक्तिगत कारणों से दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है। जिस वक्त चुनाव की तैयारियां जारी हैं। आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती व आवाजाही को लेकर गृहमंत्रालय व रेलवे के बीच महत्त्वपूर्ण बैठकें कर रहा है। उस वक्त एक साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की नवनियुक्ति होने तक नियमित कामों में व्यवधान तो डालेगी ही। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर संविधान ने विशेष जोर दिया गया है। चुनाव आयुक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते वक्त कुमार ने कहा था कि अनाचारों को रोकने व निर्वाचनों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति आयोग उत्तरदायी है। याद रखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए टीएन शेषन ने आम मतदाताओं के भीतर निर्वाचन आयोग के प्रति विशेष सम्मान का भाव जगाने का काम किया था। चुनावों के दरम्यान विपक्षी दलों व छोटे-छोटे स्थानीय दलों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वालों के अधिकारों के साथ मतदाताओं की जागरूकता व मताधिकार प्रयोग करने के प्रति सतर्कता बनाए रखना भी आयोग का ही काम है। इन नियुक्तियों में समय का ख्याल रखना जरूरी है। ताकि चुनावपूर्व की तैयारियों में किसी तरह का व्यवधान न आए।

चिंतन-मनन

इच्छा का लक्ष्य है खुशी

बुरी आदत को छोड़ने की असमर्थता तुम्हें तकलीफ देती है। जब तुम बहुत पीड़ित होते हो, वह व्यथा तुम्हें उस आदत से छुटकारा दिलाती है। जब तुम अपनी कमियों से व्यथा महसूस करते हो, तब तुम साधक हो। पीड़ा तुम्हें आसक्ति से दूर करती है। यदि अपने दुगुर्णों को हटा नहीं सकते, तो उन्हें विस्तृत कर दो। चिन्ता, अभिमान, प्रोध, कामना, दुख सबको एक और बड़ा आयाम दे दो, एक दूसरी दिशा। छोटे-छोटे विषयों पर नाराज होने का क्या तुक है? नाराज होना है तो अनन्तता के प्रति, ब्रह्म के प्रति हो। यदि तुम अपने अहंकार को नहीं खत्म कर सकते तो अहंकार करो कि ईश्वर तुम्हारे हैं। यदि आसक्ति तुम पर छाई है, तो सत्य के प्रति आसक्त हो जाओ। यदि ईर्श्या तुम्हें सताती है, तो सेवा के लिए ईर्श्या करो। द्वेष के प्रति द्वेष रखो; गुरु से राग करो। दिव्यता के प्रति मदहोश हो जाओ।

इन्द्रिय सुखों की इच्छाएं विद्युत की तरह हैं; जैसे-जैसे वे विषय विस्तुओं की ओर बढ़ती है, निष्प्रभावी हो जाती हैं। अपनी कुशलता से यदि तुम इच्छाओं को अपने भीतर मोड़ सको- अपने अस्तित्व के केन्द्र की ओर- तो तुम्हें मिलेगा एक और आयाम- चिरन्तन सुख, रोमांच, परमानन्द और शात प्रेम। वासना, लोभ और ईर्ष्या इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि ये केवल ऊर्जा हैं और तुम ही इनके स्त्रेत हो- वह विशुद्ध ऊर्जा। निष्ठा और भक्ति तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखती हैं, तुम्हें उन्नत करती हैं।

जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम स्वयं ही सुख की विद्युत धारा हो, तुम्हारी लालसाएं घटने लगती हैं और प्रशांति आती है। मृत्यु निश्चित है - यह याद रखने से तुम वर्तमान क्षण में सजीव रहते हो, राग और द्वेष से मुक्त। इच्छा खुशी को खत्म करती है, लेकिन सभी इच्छाओं का लक्ष्य है खुशी। जब भी जीवन से खुशी गायब होने लगे, भीतर गहराई में झांककर देखो- तुम पाओगे यह इच्छा के कारण हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ही केवल खुशी है। कोई जीव आज तक पैदा नहीं हुआ जिसे दुःख की चाह हो- न ऐसा पहले कभी हुआ है, न भविष्य में होगा। जब तुम्हारा छोटा मन इधर-उधर, जब जगह भागते-भागते थक जाता है, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी छीन ली है।

भाजपा की एक और तुरुप है सी ए ए...

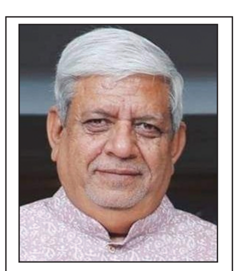

निमिषा सिंह

भाजपा का सब्र लाजबाब है। इतना सब्र भाजपा कहाँ से लाती है आखिर ? भाजपा ने आम चुनाव में उतरने से पहले कालेधन की कालिख से अपने आपको बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बांड का फैसला धूमिल करने के लिए आखिर सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। भाजपा का ये फैसला है तो विवादास्पद लेकिन है आत्मघाती फैसल। ये फैसला भाजपा की नाव पार भी लगा सकता है और नाव डूबा भी सकता है।

भाजपा ने नागरिकता संशोधन का बीज चार साल पहले ९ दिसंबर 2019 को बोया था। इस बीज को अंकुरित करने के लिए भाजपा ने चार साल तीन महीने तक चुपचाप खाद-पानी दिया और जैसे ही इलेक्टोरल बांड की आंधी ने भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करने की स्थितियां बनाईं वैसे ही भाजपा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने का ऐलान कर दिया। इस कानून के खिलाफ देश में शुरू में जो गुबार उठा था उसे भाजपा ने लंबा खींचकर पहले ही ठंडा कर दिया था ,लेकिन अब हालात बदल गए है । देश का विपक्ष भाजपा के इस दांव के सामने अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

नागरिकता कानून में संशोधन बोतल में बंद जिन्न की तरह है। भाजपा इस जिन्न के जरिये एक नहीं अनेक अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करने का इंतजाम करना छाती ह। भाजपा को पता है की पिछले एक दशक में अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक तबके भाजपा से नाराज है। निमने मुसलमान,ईसाई और सिख सभी शामिल है। अब इन समुदाय के विदेशियों के लिए नागरिकता का रास्ता आसान कर भाजपा चुनाव में इन सभी अल्पसंख्यक समूहों की सहानुभूति बटोरना चाहती है। ये दूर की कौड़ी नहीं बल्कि एक सोचा-समझा हुआ गणित है। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। आपको याद होगा की नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था।

भारत का नागरिकता अधिनयम 69 साल पुराना है । इसकी आधारशिला अंग्रेजों के जमाने की है। भाजपा इस कानून के जरिये जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की तरह नागरिकता अधिनियम में तब्दीली करने के लिए कमर कसकर बैठी हुई थी। नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

मुमकिन है कि भाजपा इस काम को पहले अंजाम देती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। लेकिन अब इसे हम लागू कर दिया गया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।भाजपा ने एक पंथ दो काज कर लिए है। एक तो इस कानून के जरिये भाजपा अपने अल्पसंख्यक प्रेम को स्थापित करने के साथ होई इलेक्टोरल बांड की पोल खुलने से होने वाली फजीहत से भी बचना चाहती है। विपक्ष अब इलेक्टोरल बांड के मुद्दे को उछाले या नागरिकता संशोधन विधेयक के इस नए मुद्दे को उछाले।

इस नए तूफान के बाद अब देश की राजनीति में नया रंग आने वाला है। विपक्ष पहले से ही सत्तारूढ़ दल की चालबाजियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है ,और अब ये नागरिकता संशोधन कानून लागू कर भाजपा ने समूचे विपक्ष को निहत्था कर दिया है। इस कानून के लागू करने में भाजपा को फिलहाल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि अभी सब चुनावी जंग में कूद रहे हैं। इस कानून पर अमल तो चुनावों के बाद से होगा,हाँ चुनावों में भाजपा इस कानून के जरिये रूठे हुए अल्पसंख्यकों के बीच अपनी खोई हुई साख बचने का प्रयास जरूर करेगी। इस संशोधन

कानून का फायद भाजपा को सीमावर्ती क्षेत्रों में मिल सकता है।

भाजपा को इस बात के लिए बधाई या शाबासी दी जा सकती है की वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आंधी के मुकाबले एक नया इंतजाम करके रखती है। आज देश की जनता महंगाई ,बेरोजगारी और दुसरे तमाम मुद्दों को भूलने की बीमारी का शिकार बन चुकी ह। अवाम को धर्म की सुरा पहले से ही पिलाई जा चुकी है। इस नशे को उतरने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना है की इस कानून को लागू कर सत्तारूढ़ दल देश के अम्नो-अमान को महफूज रख पाती है या बिगाड़ती है क्ये घोषणा माहे रमजान के समय की गयी है और इसके भी अलग निहितार्थ हैं। आगे-आगे देखिये होता है क्या ? आपको याद होगा की देश के अनेक राहों ने इस कानून का विरोध किया है और किसी भी सूरत में इस कानून को लागू न किये जाने की बात कही है। असम,केरल और बंगाल इस मुद्दे पर पहले से खिलाफ हैं।

दिल्ली मेट्रो : बददिमाग यात्रियों पर सख्ती जरूरी

डॉ. सुनील विपुल

पिछले लगभग ढ़ाई दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस एक संसाधन से सबसे ज्यादा विकसित व संपन्न हुई है, वह है दिल्ली मेट्रो। अपनी शुरूआत से ही यह अपनी खूबियों की वजह से न सिर्फ लोकप्रिय हुई बल्कि बहुत सारे कीर्तिमान भी स्थापित किए। आज मेट्रो का विस्तार न केवल दिल्ली वरन दिल्ली से लगे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम,फरीदाबाद तक हो चुका है। दिल्ली मेट्रो आए दिन चर्चा का विषय बनती रहती है कभी रिकॉर्ड यात्रियों द्वारा मेट्रो में सफर के लिए तो कभी दिल्ली मेट्रो में यात्रियों द्वारा तरह-तरह की गतिविधियों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में जब से रील कल्चर पापुलर हुआ है दिल्ली मेट्रो रील बनाने वालों का भी एक प्रमुख अड्डा बन गया है। सिंगिंग, डांसिंग से लेकर प्रैंक वीडियो तक दिल्ली मेट्रो में बिना परमिशन के शूट किए जाते रहे हैं और तमाम नियम-अधिनियम और कानूनों के बावजूद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इन्हें रोकने में असफल साबित हुआ है।

आए दिन दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकतें करते हुए कपल के वीडियो वायरल होते रहे हैं, तो कभी गाली-गलौज करते हुए कुछ यात्री। डीएमआरसी के अनुसार दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं ऐसे

में सभी पर नजर रख पाना संभव नहीं है, इसलिए यात्रियों से अपील है कि अगर वे आस-पास किसी को अश्लील हरकत करते हुए देखते हैं तो तुरंत मेट्रो ट्रेन के कोच में लगे इमरजेंसी बटन को दबाकर ट्रेन ऑपरेटर को भी इसकी सूचना दे सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 कहती है कि व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर न तो अश्लील कार्य कर सकता है न ही कोई अश्लील गाने बजा सकता है न इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों। ऐसा करते हुए पाए जाने पर उसको तीन महीने की सजा अथवा जुमार्ना या फिर दोनो हो सकता है। हालांकि इस कानून में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु कोई भी ऐसा कार्य जिसे देखकर लोग असहज महसूस करें तो वह अश्लीलता की ही श्रेणी में आता है।

अश्लीलता को परिभाषित करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, फिर भी सार्वजनिक जगहों पर नितांत निजी क्रियाओं को अश्लील कहा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 59 के तहत यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर मेट्रो के अंदर किसी प्रकार की अभद्रता या अश्लीलता करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसे मेट्रो से तुरंत उतारकर उस पर जुमार्ने के रूप में 500 रु पए दंड का भी प्रावधान है। वैसे ये नियम तब लागू होता है जब व्यक्ति नशे की हालत में हो या उसने किसी के साथ अभद्रता की हो।

दिल्ली मेट्रो में आए दिन महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कभी महिला यात्रियों से छेड़-छाड़ तो कभी उनके साथ अभद्रता की खबरें आती रहीं हैं। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हां दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रील बनाने जैसे कायरे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है और ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनके विरु द्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिर भी आए दिन चलती हुई मेट्रो में कभी तरह-तरह के स्टंट करते हुए युवा रील बना रहे हैं तो कभी अन्य सहयात्रियों की असुविधा का ध्यान रखे बिना प्रेम या चुंबन जैसे निजी क्रिया को सार्वजनिक दिखावा करते हुए पाए जा रहे हैं। ऐसा कई बार इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के लिए भी किया जाता है।

अभी पिछले दिनों दो महिलाओं की मेट्रो में हुई लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक-दूसरे को भद्दी-भद्दी गालियां दे रही हैं। क्या इस तरह की घटनाओं से बाकी सहयात्री प्रभावित नहीं होते? क्या बच्चों/युवाओं पर ऐसी घटना का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता? आए दिन मेट्रो में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ग्रुप बनाकर चोरी करने वाले गिरोह (महिला/पुरु ष दोनों) ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पर इसे भी दुर्भाग्य से रोका नहीं जा पा रहा। क्या डीएमआरसी को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं करना चाहिए?

क्या ऐसे लोगों की आगे कुछ समय के लिए मेट्रो की यात्रा करने पर रोक नहीं लगा देना चाहिए? हवाई यात्राओं में कोई यात्री दुर्०?यवहार करता पाया जाता है और ऐसा बार-बार करता है तो उसको जैसे भविष्य में कुछ माह/साल के लिए यात्रा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वैसे ही मेट्रो की यात्रा के लिए भी किया जाना वक्त की मांग है। ऐसे कृत्य के लिए फिलहाल दंड या जुमार्ने का प्रावधान नाकाफी है। यात्रियों की बेहतरी, सुरक्षा और निजता की रक्षा के लिए डीएमआरसी को अपने प्रावधानों में बदलाव करना चाहिए। निश्चित तौर पर इन सुधारों से दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी लाइन, सर्वाधिक यात्रियों के साथ सबसे बेहतर और सुरक्षित सुविधा वाली सेवा साबित होगी।

डॉक्टरों और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों को उपहार और फ्री सैंपल देने पर लगेगी रोक

- सरकार ने फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस को लेकर नोटिफाई किया यूनिफॉर्म कोड

नई दिल्ली ।

फार्मा सेक्टर में दवाओं और फार्मा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कई कंपनियां डॉक्टरों और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों को उपहार और अन्य सुविधाएं देती आ रही थी। सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है। सरकार ने फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस को लेकर यूनिफॉर्म कोड यानि यूसीपीएमपी 2024 को नोटिफाई कर दिया है। इस कोड में मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियों के मद्देनजर कंपनियों, डॉक्टरों, हेल्थकेयर से जुड़े लोगों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हाल ही में जारी इस दिशानिर्देश में कंपनियों को विदेशों में चिकित्सा शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने से रोक लगाई गई है। इसी के साथ कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ऐसी कार्यशालाओं के बारे में पूरा विवरण भी बताना होगा, जिसमें उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा शामिल है। कंपनियां स्वतंत्र या जोखिम-आधारित ऑडिट के अधीन हो सकती हैं। कोड में ये बताया गया है कि इन गाइडलाइन्स का पालन करने के लिए फार्मा कंपनी के सीईओ जिम्मेदार होंगे और हर वित्त वर्ष के खत्म होने पर दो महीने के भीतर फार्मा कंपनी के कार्यकारी द्वारा एसोसिएशन को इसे लेकर सेल्फ डिक्लरेशन दी जाएगी। इस डिक्लेरेशन को एसोसिएशन की वेबसाइट या फिर सीधे यूसीपीएमपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कोड के अनुसार, फार्मा कंपनियों या उनके प्रतिनिधि हेल्थकेयर प्रोफेशनल या उनके परिवार के सदस्यों को देश में या बाहर घूमने की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकते। इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल या उनके परिवार के सदस्यों को कैश आदि भी नहीं दिया जा सकता। कंपनियां अगर डॉक्टरों को फ्री सैंपल दे रही हैं तो उन्हें इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही कंपनियां सालाना घरेलू बिक्री का 2 फीसदी से ज्यादा फ्री सैंपल के रूप में नहीं बांट सकती है।

फ्लिपकार्ट भी बड़े शहरों में बनाएगी हजारों डार्क स्टोर

- कंपनी स्टोर स्थापित करने उद्यमियों एवं किराना दुकानों से कर रही है बात

नई दिल्ली ।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट देश के बड़े शहरों में हजारों डार्क स्टोर स्थापित की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार वॉलमार्ट नियंत्रित फ्लिपकार्ट अगले कुछ महीनों में लोगों का ऑर्डर किया सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाने की तैयारी कर रही है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में डार्क स्टोर उन किराना स्टोर को कहा जाता है, जो ऑर्डर मिलने के बाद झट से सामान ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए खोले जाते हैं। कंपनी ऐसे स्टोर स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्यमियों एवं किराना दुकानों से बात कर रही है। मगर कंपनी इन डार्क स्टोर पर मालिकाना नियंत्रण नहीं रखेगी। कंपनी के इस कदम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। एक सूत्र ने कहा कि इन दिनों सभी का जोर ग्राहकों के ऑर्डर जल्द से जल्द पहुंचाने पर है। फ्लिपकार्ट को मालूम है कि बाजार में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए उसे समय के साथ अपनी तैयारी भी दुरुस्त रखनी होगी। ग्राहकों तक कम से कम समय में ऑर्डर पहुंचाना कंपनी की इसी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी के पास ऐसे ऑर्डर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनमें ग्राहक मनमाफिक सामान कम से कम समय में पाना चाहते हैं। ऐसे ऑर्डर फल-सब्जियों एवं अनाज ही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर सजाने के सामान और वेलनेस की चीजों के लिए भी आ रहे हैं क्योंकि लोग अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। फ्लिपकार्ट ने हाल में अपनी मूल कंपनी वॉलमार्ट एवं दूसरे निवेशकों से 60 करोड़ डॉलर रकम जुटाई थी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी कुल 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों से बातचीत कर रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपूर्ति क्षमता बढ़ाने और 20 शहरों में ऑर्डर मिलते ही उसी दिन सामान पहुंचाने जैसी सुविधाओं पर बड़े निवेश किए हैं।

पेटीएम एनएचएआई की सूची से बाहर

एनएचएआई की संशोधित सूची में 39 बैंकों के नाम शामिल

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से पेटीएम पर लगाई गई रोक के बाद अब नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की लिस्ट को रिवाइज कर दिया है। एनएचएआई द्वारा जारी की गई फास्टैग इश्यू करने वालों की सूची में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का नाम नहीं है। ग्राहक अब पेटीएम से फास्टैग नहीं ले पाएंगे। एनएचएआई की संशोधित सूची में केवल 39 बैंकों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनसे फास्टैग लिया जा सकता है। इस सूची में ऑथराइज्ड बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नाम हैं। अब फास्टैग इन बैंकों से ले सकेंगे- एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। एनबीएफसी की सूची में- इलाहाबाद बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, कॉसमॉस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक, जेएंडके बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, लिवक्विक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, सारस्वत बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, द जलगांव पीपुल्स कंपनी -ऑप बैंक, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक और यूको बैंक आदि एनबीएफसीएस शामिल हैं।

मारुति रेलवे के जरिये सालाना 3,00,000 कारों की ढुलाई कर सकेगी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों हंसलपुर संयंत्र में भारत की पहली इन-प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उदघाटन किया। इसकी बदौलत मारुति रेलवे के जरिये सालाना 3,00,000 कारों की ढुलाई कर सकेगी। इस पूरी परियोजना की लागत 1,081 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहें तो भले ही हमें इस परियोजना के कारण कुछ न बच रहा हो, लेकिन फिर भी हमें काफी खुशी होगी क्योंकि इससे हमें बड़ा पैमाना मिल रहा है। यह कारों की ढुलाई का बहुत ही सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ तरीका है। अगर रेल का बुनियादी ढांचा नहीं होता तो हमें क्षमता संबंधी बाधा झेलनी पड़ती। वित्तीय बचत के बिना भी यह कारों के परिवहन का बेहतर तरीका है। इस नई लाइन का परिचालन साल 2026-27 से शुरू होगा। साल 2023-24 के पहले 11 महीने के दौरान मारुति ने रेलवे के जरिये 4,09,000 गाड़ियों की ढुलाई की थी जबकि शेष गाड़ियां सड़क मार्ग से भेजी गई थीं। नई लाइन के कारण इसमें काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा` कि एक रेक (ट्रेन) 270 से 300 कारें ले जाती है और इसलिए यह 40 ट्रकों का स्थान ले लेती है। इसलिए नई रेलवे साइडिंग के कारण लगभग 50,000 ट्रकों के फेरे कम हो जाएंगे जिससे हमें 3.5 करोड़ लीटर जीवाश्म ईंधन बचाने में मदद मिलेगी।

गूगल ने झूठी सूचना के प्रसार को रोकने निर्वाचन आयोग से किया समझौता

नई दिल्ली ।

अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने आगामी चुनाव के दौरान झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग से समझौता किया है। गूगल इंडिया ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इसके उत्पाद चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधिकारिक सूचना बढ़ाने की विशेषताओं से लैस किये गए हैं। गूगल ने कहा कि हम मतदान के बारे में गूगल सर्च पर अंग्रेजी और हिंदी में महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढने में लोगों की सहायता के लिए सहयोग कर रहे हैं। इन जानकारियों में पंजीकरण कैसे करें और मतदान कैसे करें शामिल हैं। अधिक संख्या में लोगों के कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल करने के विषय पर गूगल ने कहा कि यह ऐसी प्रक्रियाएं तैयार कर रही है जो उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम मेधा सामग्री की पहचान करने में मदद करेगी। इसने कहा कि अधिक विज्ञापनदाताओं द्वारा एआई की शक्ति और अवसर का लाभ उठाये जाने पर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अधिक पारदर्शिता और विषय पर सभी जानकारियों के साथ लोगों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देते रहें। गूगल ने कहा कि हमारी विज्ञापन नीतियां पहले से ही

गुमराह करने वाली डीपफेक या छेड़छाड़ की गई सामग्री के उपयोग को निषिद्ध करती हैं। गूगल ने इस बारे में कड़ी नीतियां एवं पाबंदियां निर्धारित की हैं कि चुनाव संबंधित विज्ञापन उसके मंचों पर कौन जारी कर सकता है। इनमें निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान का सत्यापन, प्रमाणन और अधिकृत किया जाना शामिल है।

बड़ी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा नियमन का सुझाव

नई दिल्ली। सरकार की एक समिति ने बड़े डिजिटल उद्यमों के लिए नियमन का प्रस्ताव दिया है। इसका उददेश्य इन क्षेत्रों में किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति (सीडीसीएल) ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट और नियमों का मसौदा जारी किया। इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई हैं। समिति का गठन पिछले साल फरवरी में किया गया था। उससे पहले, संसद की समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसके बाद समिति का गठन किया गया। समिति ने अन्य बातों के अलावा, नियमन के मसौदे के तहत दायित्वों के लिए सिद्धांत-आधारित रूपरेखा का सुझाव दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि समिति ने बड़े डिजिटल उद्यम यानी तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बाजार में उनकी गतिविधियों की सक्रिय निगरानी के लिए नियमों की सिफारिश की है।

डाबोलिन हवाई अड्डा से उड़ानों का परिचालन जारी रहेगा: अधिकारी

पणजी । डाबोलिम स्थित गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जीआईए) के प्रबंधन का कहना है` कि इस हवाई अडडे को अभी बंद नहीं` किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन जारी रहेगा। इन खबरों के बीच कि एक निजी एयरलाइन अपना परिचालन दक्षिण गोवा जिले में डाबोलिम स्थित हवाई अड्डे से उत्तरी गोवा जिले के मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एमआईए) में स्थानांतरित कर रही है, विपक्षी कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हाल में गोवा विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने दावा किया था कि जीआईए में महंगी परिचालन लागत के कारण उड़ान परिचालन को एमआईए में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जीआईए के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि डाबोलिम हवाई अड्डे का विकास जारी रहेगा क्योंकि इसमें अच्छी संभावनाएं हैं। दक्षिण गोवा में वास्को शहर के पास स्थित जीआईए नौसेना के आईएनएस हंसा बेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि डाबोलिम हवाई अड्डे पर परिचालन लागत अधिक है। यह एक गलत धारणा है। उन्होंने कहा कि डाबोलिम हवाई अड्डे को बचाने के नाम पर कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं जिससे इसकी संभावनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि डाबोलिम हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क एमआईए की तुलना में कम है और इसकी परिचालन लागत भी कम है।

जेजी केमिकल्स का शेयर पांच फीसदी गिरकर सूचीबद्ध

नई दिल्ली । जेजी केमिकल्स लिमिटेड का शेयर बुधवार को अपने 221 रुपये के निर्गम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक गिरकर सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य पर 4.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 211 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में यह 11.26 प्रतिशत गिरकर 196.10 रुपये पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 5.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 209 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 772.16 करोड़ रुपये रहा। जेजी केमिकल्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को गुरुवार को बोली के आखिरी दिन 27.78 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 251.2 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 210-221 रुपये प्रति शेयर था। जिंक ऑक्साइड विनिर्माता के आईपीओ में 165 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए थे। इसमें 39 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल है।

भारतीय उच्चायोग सिंगापुर से भारत में अधिक निवेश लाने कर रहा कामः अंबुले

सिंगापुर । भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने कहा कि भारतीय उच्चायोग सिंगापुर से भारत में अधिक से अधिक निवेश के लिए काम कर रहा है। अंबुले ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने आक्रामक तरीके से बढ़ गया है, ऐसे में हम भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयास में हैं। उच्चायुक्त ने वृद्धि को गति देने वाले तीन कारकों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के साथ भारत के लिए यह हरित वृद्धि होगी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के सुगम प्रवाह के लिए डिजिटल ढांचा बनाया गया है। साथ ही भारत की सतत वृद्धि भी एक कारक है जिसकी वजह से उसे निवेश मिलेगा। उच्चायुक्त ने मंगलवार देर शाम यहां 2024 बजट विश्लेषण-सिंगापुर और भारत कार्यक्रम में कहा कि हम सिंगापुर से भारत में अधिक निवेश लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाली आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला पर भी प्रकाश डाला। इसमें युवाओं को कुशल बनाने का प्रयास, सेमीकंडक्टर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास और महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास शामिल है।

फरवरी में खुदरा महंगाई 5.09 प्रतिशत रही

नई दिल्ली । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी, 2024 में मामूली घटकर 5.09 प्रतिशत पर आ गई जबकि इससे पिछले महीने में यह 5.10 प्रतिशत रही थी। पिछले साल फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.44 प्रतिशत थी। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर फरवरी में पिछले महीने की तुलना में लगभग स्थिर 5.09 फीसदी पर रही। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई जनवरी में 5.1 फीसदी और एक साल पहले की समान अवधि में फरवरी 2023 में यह 6.44 फीसदी थी। फरवरी में फूड बॉस्केट में खुदरा महंगाई 8.66 फीसदी थी, जो पिछले महीने के 8.3 फीसदी से मामूली ज्यादा थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को मंहगाई को दो फीसदी घटबढ़ के साथ चार फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीपीआई आधारित महंगाई 5.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था और जनवरी-मार्च तिमाही में 5 फीसदी दर्ज किया गया था।

शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद, सेंसेक्स 906 अंक नीचे आया

निफ्टी 21,997.70 के स्तर पर फिसला

मुम्बई । घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गयी। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी होने से बाजार टूटा। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 906.07 करीब 1.23 फीसदी की गिरावट के साथ ही 72,761.89 और निफ्टी में भी 1.51 फीसदी तकरीबन 338.00 अंकों की गिरावट रही और ये 21,997.70 के स्तर पर बंद हुआ।

स्मॉलकैप इंडेक्स में भी आज 2200 अंक से ज्यादा की गिरावट रही और ये 40,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं मिडकैप में 1,800 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गयी। ये 37,420 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही। जेट एयरवेज के शेयर में आज लगातार दूसरे दिन 5 फीसदी की बढ़त रही।

वहीं बीएसई स्मॉलकैप के शेयरों में आज 5 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने में आई है। मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में आज इसलिए दबाव रहा क्योंक बाजार नियामक एजेंसी सेबी अध्यक्ष ने छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों की ऊंची कीमतों को सही नहीं बताया था। उन्होंने कहा सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 7 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी। इसके अलावा, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती

एयरटेल, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर भी गिरे हैं। वहीं दूसरी ओर आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक के शेयर ऊपर आये हैं। वहीं गत दिवस बढ़त पर बंद हुआ था। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजारों से मिले अच्छे संकेतों की वजह से बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 247.61 अंक तेज होकर 73,915.57 पर और निफ्टी 61.70 अंक ऊपर 22,397.40 पर कारोबार कर रहा था। इसके कुछ समय बाद ही बाजार में गिरावट आने लगी जो अंत तक बनी रही।

जनवरी में भारत का औद्योगिक उत्पादन 3.8 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली । भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर आई है। साल 2024 के पहले महीने जनवरी में भारत का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) पिछले साल के मुकाबले 2 फीसदी घटकर 3.8 फीसदी हो गया है। गौरतलब है कि पिछले साल की समान अवधि जनवरी 2023 में यह 5.8 फीसदी था। बता दें कि आईआईपी वह डेटा होता है जिसके जरिये औद्योगिक उत्पादन मापा जाता है। एनएसओ के डेटा से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट आई है। पिछले साल जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऑउटपुट 4.5 फीसदी था, जो जनवरी 2024 में घटकर 3.2 फीसदी हो गया है। जनवरी 2024 में खे निज उत्पादन 5.9 फीसदी बढ़ा। पिछले साल के मुकाबले इसमें 3.1 फीसदी की कमी आई है। जनवरी 2023 में खे निज उत्पादन 9 फीसदी पर था। डेटा से पता चलता है कि पावर ऑउटपुट 5.6 फीसदी बढ़ा है। जबकि पिछले साल की समान अवधि में इलेक्ट्रिसिटी ऑउटपुट 12.7 फीसदी था।

पांच साल में भारत डेकाथलॉन के पांच वैश्विक बाजारों में शामिल होगा

- डेकाथलॉन भारत में हर साल 10 नए स्टोर खोलेगी

पेरिस ।

फ्रांस की खेल क्षेत्र की रिटेलर डेकाथलॉन ने कहा कि उसके लिए भारत एक बड़ी प्राथमिकता वाला बाजार है। स्टोर नेटवर्क के विस्तार और स्थानीय सोर्सिंग बढ़ने के साथ अगले पांच साल में भारत उसके शीर्ष पांच वैश्विक बाजारों में शामिल होगा। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है। कंपनी के एक मुख्य रिटेल एंड कंट्रीज ऑफिसर ने कहा कि डेकाथलॉन अपनी वृद्धि की योजनाओं के तहत भारत में हर साल 10 नए स्टोर खोलेगी। नए स्टोर 1,000 से 2,000 वर्ग मीटर के बीच के छोटे स्टोर हो सकते हैं। इसके अलावा ये 4,000 वर्ग मीटर में फैले बड़े स्टोर भी हो सकते हैं। साथ ही कंपनी का इरादा ऑनलाइन बिक्री में तेजी लाने और अगले पांच साल में स्थानीय सोर्सिंग को मौजूदा के औसतन 60 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का है। इस कदम से डेकाथलॉन को तेजी से बढ़ते भारतीय खेल और एथलेजर खंड में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी और इसकी भारतीय विनिर्माण सुविधा से वैश्विक बाजारों में निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने यहां डेकाथलॉन के वैश्विक कार्यक्रम में कहा कि भारत हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता है। हमारे पास पांच देश हैं, जिन्हें हम लंबी छलांग वाला देश कहते हैं। भारत उनमें से एक है। डेकाथलॉन के लिए भारत पहले से राजस्व के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बाजारों में है। हम इसे शीर्ष पांच में लाना चाहते हैं। यह अगले पांच साल में होगा। डेकाथलॉन इंडिया का कारोबार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,995 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि हम हर साल 10 स्टोर खोलना चाहते हैं। इस समय हम अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। हम डिजिटल रूप से खुद को स्थापित कर रहे हैं। हम बड़े फॉर्मेट स्टोर के साथ बड़े शहरों में छोटे स्टोर पर भी काम कर रहे हैं।

खेल

एफआईएच विश्व रैंकिंग: भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे, महिला टीम नौवें स्थान पर खिसकी

नई दिल्ली । एफआईएच विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक स्थान के नुकसान के साथ ही चौथे जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर खिसक गयी है। जर्मनी की टीम ओलंपिक क्वालीफायर्स में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2761 रैंकिंग अंक हैं। उसने पिछले साल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी जगह बना ली है। इस कारण उसे ओलंपिक क्वालीफायर्स में भाग नहीं लेना पड़ा। वहीं जर्मनी की टीम ओमान में खेले गए ओलंपिक क्वालीफायर्स में सभी मैच जीतकर 2786 अंक हासिल करने में सफल रही है। इससे वह विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम से आगे हो गयी है। वहीं नीदरलैंड 3060 अंक लेकर नंबर एक पर बनी हुई है। बेल्जियम 2848 अंक लेकर दूसरे जबकि जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2757 अंक हैं। वहीं इंग्लैंड के 2720 अंक हैं और वह 5 वे स्थान पर है। अर्जेंटीना 2524 अंक और स्पेन 2296 अंक लेकर पहले की तरह ही 7वें और 8वें स्थान पर बने हुए हैं। फ्रांस के भी 2085 अंक हैं जबकि न्यूजीलैंड के 2025 अंक हैं। वहीं महिला वर्ग में भारतीय टीम 2215 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। महिला वर्ग में नीदरलैंड 3422 लेकर नंबर एक पर है जबकि अर्जेंटीना 2827 अंक के साथ ही दूसरे नंबर पर है। जर्मनी 2732 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया

गाजियाबाद ।

भविष्य में गाजियाबाद में भी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच खेले जाएंगे। इसके लिए यहां एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इस स्टेडियम का शिलान्यास भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) द्वारा विकसित की जाने वाली एक परियोजना की आधारशिला भी रखी। स्टेडियम के निर्माण में देरी का कारण क्षेत्र में हाई टेंशन बिजली के तारों और खंभों को बताया गया है। शुक्ला ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में कोई स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस पर नाराजगी जतायी कि जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने के बाद भी विभाग ने दो बिजली लाइनें लगा दी गईं थीं। यह क्षेत्र उड़ान क्षेत्र में भी पड़ता है, इसलिए भारतीय वायुसेना से भी इस योजना की मंजूरी

देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं स्टेडियम के शिलान्यास पर यूपी के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि इसका निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा कि 450 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाला ये स्टेडियम 32 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसमें एक समय में 55,000 लोग बैठ सकेंगे। स्टेडियम का निर्माण अगले दो साल यानी 2026 तक पूरा होने की संभावना है। जरूरत और आधुनिकता को देखते हुए पिछले 9 साल में प्रोजेक्ट के बजट में करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभ में, परियोजना की लागत 350 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

भारत पेरिस ओलंपिक में एक से अधिक भाला फेंक पदक जीत सकता है किशोर जेना

चंडीगढ़,

उभरते भाला फेंक स्टार किशोर कुमार जेना, जो मई में दोहा में डायमंड लीग से अपने आउटडोर सीज़न की शुरुआत करेंगे, ने कहा है कि वह नीरज चोपड़ा को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अब 130 दिन से कुछ अधिक दूर हैं और जेना ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ इसे देश के लिए यादगार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जेना, जो वर्तमान में पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) में प्रशिक्षण ले रहे हैं, ने कहा, भारत पेरिस में एक से अधिक भाला फेंक पदक जीत सकता है। पिछले साल बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स मीट में नीरज चोपड़ा के साथ आमने-सामने होने के बाद से जेना सुर्खियां बटोर रहे हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार, चोपड़ा और किशोर कुमार जेना ने हांगझोउ 2023 में भाला फेंककर इसे एक-दो कर दिया। पेरिस के लिए क्वालीफाई करने के बाद, जेना को लगता है कि भाला फेंक में पदक की संभावनाएं केवल चोपड़ा तक ही सीमित नहीं हैं। नियम के अनुसार, भाला फेंक में एक देश से तीन खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इससे पेरिस में अधिक पदक जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जेना ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) से कहा, हम सभी ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर हम चोट मुक्त रह सकते हैं, तो भारत टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जेना, जो ओडिशा के पुरी जिले के एक किसान परिवार से आते हैं, पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में एक एक्सपोज़र ट्रिप के लिए गए थे, जहाँ उनके साथ लंबे समय के कोच समरजीत सिंह माल्ही भी थे। उन्होंने अपनी कोर और कंधे की ताकत को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वेट ट्रेनिंग की। यह पूछे जाने पर कि वह दोहा प्रतियोगिता में क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं , जेना ने कहा, मैंने अब तक इसके (90 मीटर) बारे में नहीं सोचा है। मेरा लक्ष्य अपने परिणामों में सुधार करना और अपनी कमजोरियों पर काबू पाना है। मैं नीरज से सुझाव लेता रहता हूं. मैं उन्हें अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखता. जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो मैं उनकी सलाह लेता हूं क्योंकि वह उन सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। जब सही सुझाव देने की बात आती है तो वह पीछे नहीं हटते। हांग्जो एशियाई खेलों के दौरान, चोपड़ा के लिए थोड़ा डर था क्योंकि अधिकारियों ने उनके पहले अच्छे

थ्रो पर विचार नहीं किया था। बाद में, जेना ने 87.54 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चोपड़ा को अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित किया। ओलंपिक चैंपियन अंततः अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए 88.88 मीटर के विशाल थ्रो के साथ आए।

जेना को रजत पदक मिला और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाइंग मार्क हासिल किया। उस समय मुझे खुशी थी कि मैंने पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

वापसी को लेकर उत्साहित और घबराया हुआ हूं : ऋषभ

नई दिल्ली ।

आईपीएल से वापसी करने जा रहे आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह पदार्पण करने जा रहे हों। वहीं इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस बल्लेबाज को फिट करार देते हुए कहा कि वह आईपीएल खेल सकते हैं। साथ ही कहा कि उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स 23 मार्च को मोहाली में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ऋषभ दिसंबर 2022 में एक कार हादसे में गंभीर रुप से घायल हो गये थे। उसके बाद उन्हें सर्जरी से भी गुजरना पड़ा है। सवा साल बाद मैदान पर वापसी करने जा रहे इस क्रिकेटर ने कहा, मैं उत्साहित और घबराया हुआ हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फिर से पदार्पण करने जा रहा हूं।उन्हें चोट से उबरने के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा है। इस क्रिकेटर ने कहा, मैं जो कुछ झेल चुका हूं उसके बाद फिर से क्रिकेट खेलने में सक्षम होना आसान नहीं है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों और प्रशंसकों के साथ ही बीसीसीआई और एनसीए के कर्मचारियों का आभारी हूं। उनके प्यार और समर्थन से ही मुझे वापसी में सहायता मिली है। दिल्ली कैपिटल्स प्री-सीजन कैंप में शामिल होने पर इस क्रिकेटर ने कहा, मैं दिल्ली कैपिटल्स और आईपीएल में वापसी का बेसब्री से

इंतजार कर रहा हूं। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका मैं बहुत आनंद लेता हूं। हमारी टीम के मालिक और सहयोगी स्टाफ पूरे समर्थन के साथ मेरे साथ रहे हैं। हर कदम पर मार्गदर्शन और सहयोग मिला, जिसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। मैं अपने डीसी परिवार के साथ फिर से जुड़ने और प्रशंसकों के सामने फिर से खेलने का इंतजार नहीं कर सकता।

अफगानिस्तान ने तीसरे एकदिवसीय में आयरलैंड को हराकर सीरीज जीती

शारजाह ।

अफगानिस्तान ने यहां हुए तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में आयरलैंड को 117 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही अफगानिस्तान टीम ने सीरीज भी 2-0 से जीत ली है। इस सीरीज का एक मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था। इस मैच में अफगान टीम की जीत में मोहम्मद नबी की अहम भूमिका रही। नबी ने कुल पांच विकेट लिए। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड टीम ने अफगान टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत की गुरबाज ने 51 रन जबकि जादरान ने 22 रन बनाये।

सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद शाहिदी ने 69 रन बनाकर पारी को संभाला। शाहिदी के बाद नबी ने 48 रन बनाये। इस प्रकार अफगान टीम ने नौ विकेट पर कुल 236 रन बनाये। वहीं आयरलैंड की ओर से मार्क अडायर ने तीन विकेट जबकि बैरी मैक्कार्थी ने 2 विकेट लिए। वहीं इसके अलावा थियो वान वोर्कोम, एंडी मैकब्राइन और हैरी टेक्टर ने एक-एक विकेट लिया। इसके बाद जीत के लिए मिले 237 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में आयरिश टीम सफल नहीं रही। नबी के पांच विकेट और नांग्याल खरोती के चार विकेट की सहायता से अफगानिस्तान ने आयरिश टीम को 35 ओवर में ही 119 रनों पर आउट कर दिया।

ऋषभ आने वाले समय में देश को गौरव बढ़ाएगा : धवन

सकारात्मक रवैये और कड़ी मेहनत से ही वापसी संभव हुई

नई दिल्ली ।

अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा है कि आने वाले समय में आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत देश का नाम रौशन करेंगे। धवन ने कहा कि भीषण कार हादसे से उबरकर जिस प्रकार से ऋषभ ने फिटनेस हासिल की है। उससे उसके सकारात्मक रवैए का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कारण अब वह आईपीएल से मैदान पर वापसी कर रहा है। धवन ने कहा कि कार हादसे के बाद हुई सर्जरी के कारण उसे इतना दर्द था कि वह कुछ महीनों तक कुछ नहीं कर पाता था। इसके बाद भी उन मुश्किल दिनों में उसने काफी धैर्य बनाये रखा। इसके साथ ही सकारात्मकता और सहनशीलता दिखाई जिससे आज वह ठीक हो पाया है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर उसे ताकत मिली और मुझे पूरा भरोसा है कि वह चलकर देश का नाम और रोशन करेगा। साथ ही कहा कि मैं इस युवा की वापसी से बेहद खुश हूं और उसे खेलते हुए देखना चाहता हूं।

भगवान की कृपा से वह इतनी बड़ी दुर्घटना से उबरने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने कड़ी मेहनत की और सकारात्मक रवैया अपनाये रखा। इस युवा को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, जिसमें वह दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेगा। चोटिल होने के कारण वह दिसंबर 2022 से ही मैदान से बाहर था।

साथ ही कहा कि उसके यह आईपीएल बेहद खास रहेगा क्योंकि इसमें प्रदर्शन के आधार

पर ही बीसीसीआई आगामी टी20 विश्व कप के लिए उसे टीम में जगह देने पर फैसला कर सकता है। टी20 विश्व कप में विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन भी दावेदार हैं पर इसके बाद भी ये बल्लेबाज दावेदारी में पीछे नहीं है।

टी20 विश्वकप के लिए विराट की जगह किसी युवा को मिल सकता है अवसर

मुम्बई । अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले विश्वकप में शायद ही खेल पायें। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई विश्वकप के लिए टीम सदस्यों की जो पहली सूची भेजने जा रही है उसमें विराट का नाम नहीं है। प्रत्येक विश्व कप से पहले सभी प्रत्येक क्रिकेट बोर्डों को टीम सदस्यों की एक सूची आईसीसी को देनी होती है जिसमें काफी कम बदलाव होता है। ऐसे में अगर विराट का नाम इस लिस्ट में नहीं हुआ तो उनके लिए अंतिम सूची में जगह बनाना कठिन हो जाएगा। टी20 विश्व कप 2 से 29 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। इसमें विराट की जगह किसी युवा खिलाड़ी को अवसर मिल सकता है। टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार चयनकर्ताओं का मानना है कि कोहली टी20 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं , ऐसे में उन्हें शामिल किया जाना ठीक नहीं रहेगा हालांकि अगर कोहली आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके नाम पर विचार हो सकता है। वह वैसे भी पिछले कुछ समय से खेल से दूर हैं। विराट निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से भी बाहर रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी आईपीएल में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही रहेगी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी विराट से बात की है। माना जा रहा है कि विराट की जगह पर बोर्ड किसी युवा खिलाड़ी को अवसर देना चाहता है।

संक्षिप्त समाचार

आईसीसी रैंकिंग : अश्विन एक बार फिर बने नंबर वन

दुबई । भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर आर अश्विन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा गेंदबाजी रैंकिंग में एक बार फिर नंबर एक पर पहुंच गये हैं। अश्विन पहली बार दिसंबर 2015 में नंबर वन बने थे। अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतर प्रदर्शन का लाभ मिला है। अश्विन ने अंतिम टेस्ट में नौ विकेट लिए हैं। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में पहली पारी में चार जबकि दूसरी में पांच विकेट लिए थे। इस मैच के साथ ही सीरीज में जीत से भारतीय टीम भी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है। अश्विन के शीर्ष पर पहुंचने के साथ ही भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर फिसल गये हैं। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव अंतिम मैच में सात विकेट लेने के साथ ही 15 स्थान के लाभ के साथ ही 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पांच पायदान के लाभ के साथ ही छठे स्थान पर जबकि शुभमन गिल 11 स्थान के लाभ के साथ ही अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 20वें स्थान पर पहुंच गये हैं। दो दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दो पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। सलामी बल्लेबाज, जायसवाल ने नौ टेस्ट के बाद 740 रेटिंग अंक हासिल किये हैं। इससे पहले केवल दो बल्लेबाजों ऑस्ट्रेलियाई डॉन ब्रैडमैन 752 और माइक हसी 741 को इतने रेटिंग अंक मिले थे। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली और जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी रैंकिंग में एक-एक पायदान ऊपर आये हैं। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर 11 पायदान आगे बढ़कर 71वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड पर 2-0 से श्रृंखला जीतकर डब्ल्यूटीसी तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया।

कनेरिया ने सीएए लागू होने पर खुशी जतायी

लाहौर । पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत सरकार के सीएए कानून को लागू करने का समर्थन किया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने में आसानी होगी। कनेरिया ने कहा कि वह भी इससे काफी खुश हैं। कनेरिया ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। भारत सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को वह धन्यवाद देते हैं। कनेरिया ने कहा, यह अच्छी बात है, इससे सभी को लाभ होगा। मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत अच्छा कदम उठाया। यह अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। साथ ही कहा कि एक हिंदू और सनातनी होने के नाते, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। साथ ही कहा कि मेरा भगवान हनुमान और भगवान राम के साथ गहरा संबंध है।

जोकोविच बीएनपी परिबास ओपन में उलटफेर का शिकार हुए , लुका नार्डी ने हराया

महिला वर्ग में गॉफ ,सबालेंका जीती

इंडियन वेल्स । सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच यहां जारी बीएनपी परिबास ओपन टेनिस में उलटफेर का शिकार हुए हैं। युवा खिलाड़ी लुका नार्डी ने जोकोविच को तीसरे दौर में ही तीन सेट तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-3 से हरा दिया। नार्डी ने ऐस के साथ जीत हासिल की। नार्डी को मुख्य ड्रॉ में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचवेरी की जगह शामिल किया गया था। उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी। नार्डी अब ग्रैंडस्लैम या एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर के टूर्नामेंट में जोकोविच को हराने वाले सबसे अधिक रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गये हैं। इससे पहले साल 2008 में विश्व के 122वें नंबर के खिलाड़ी केविन एंडरसन ने जोकोविच को हराया था। वहीं महिला एकल में कोको गॉफ ने लूसिया ब्रोनजेटी को सीधे सेट में 6-2, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। गॉफ ने इस प्रकार 11 में से 10 ब्रेक अंक बचाये हैं। वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन एरिना सबालेंका ने ब्रिटेन की ऐमा राडुकानु को 6-3, 7-5 से हराकर अगले दौर में जगह बनायी। वहीं पुरुष वर्ग में सातवें वरीयता प्राप्त होल्गर रूने ने लोरेंजो मुसेटी को 6-2, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी और दूसरे दौर में चोट के कारण मिलोस राओनिक के हटने पर उन्हें तीसरे दौर में प्रवेश मिला।

धर्मशाला टेस्ट में बेयरस्टो की शुभमन से बहस मेरे कारण हुई: एंडरसन

मुम्बई । इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जिम्मी एंडरसन ने कहा है कि धर्मशाला टेस्ट के दौरान जॉनी बेयरस्टो की भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल से बहस हुई थी। साथ ही कहा कि इसका कारण मैं था। इसका कारण ये है कि शुभमन ने उन्हें रिटायर होने के लिए कह दिया था। इसपर बेयरस्टो नाराज हो गये थे। एंडरसन ने माना कि पहले उन्होंने बहस शुरु की थी। एंडरसन ने टेस्ट सीरीज के दौरान ही अपने 700 विकेट भी पूरे किये हैं। इंग्लैंड की टीम को इस सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। एंडरसन ने कहा कि मैंने उनसे कुछ ऐसा कहा कि क्या आप भारत के बाहर कोई रन बनाते हैं? और उन्होंने मुझसे कहा कि यह संन्यास लेने का समय है। फिर दो गेंद बाद मैंने उसे आउट कर दिया। बता दें कि टेस्ट फॉर्मेट में शुभमन की भारत में औसत 40 जबकि विदेशों में केवल 30 है। बेयरस्टो ने सबसे पहले शुभमन से पूछा था कि आपने एंडरसन से रिटायर होने के बारे में क्या कहा? इस पर शुभमन ने कहा, मैंने उनसे कहा कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। इसपर बेयरस्टो ने भी शुभमन से कहा कि सीरीज में वह अधिक शतक नहीं लगा पाये।

खूंखार कुत्तों के पालने पर लग सकता है प्रतिबंध, नस्लें की चिन्हित

नई दिल्ली। भारत में विदेशी कुत्तों की नस्ले ज्यादा खूंखार हो जाती है। इंसानों के लिए खतरा बन रहे इन कुत्तों को लेकर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ये कुत्ता भारत के क्लाउड में फिट नहीं हो पाते हैं आक्रमक होने लगते हैं। ऐसे कई हादसे हुए है जिसमें कुत्तों ने इंसानों को मार डाला।केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, वोल्फ डॉग, मास्टिफ्स जैसे विदेशी नस्ल के कुत्तों के आयात, ब्रीडिंग और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाए। एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने यह सलाह दी है। समिति का कहना है कि इन विदेश नस्लों के कुत्ते खतरनाक हैं और भारत की परिस्थितियों में उग्र हो जाते हैं। केंद्र की राय है कि इन कुत्तों के अलावा मिक्स और क्रॉस ब्रीड के अन्य कुत्तों पर भी रोक लगाई जाए। राज्यों को लिखे खत में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने स्थानीय निकायों से अपील की है कि क्रॉस ब्रीडिंग और विदेशी नस्ल के कुत्तों को लाइसेंस या परमिट जारी न करें। इन कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग पर भी रोक लगाई जाए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की एक कमिटी गठित की गई थी। डिपार्टमेंट का कहना है कि इन नस्लों के जिन कुत्तों को पहले से ही लोग रख रहे हैं, उनकी नसबंदी करानी होगी। ऐसा इसलिए ताकि उनकी नस्ल के और कुत्ते न पैदा हो सकें। क्रॉस, मिक्स्ड और विदेशी ब्रीड के जिन कुत्तों पर रोक की सिफारिश की गई है, उन कुत्तों में पिटबुल टेरियर,तोसा इनु,अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलिरियो,डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएसबोएल,कनगाल,सेंट्रल एशियन शेफर्ड, काकेशियन, शेफर्ड,साउथ रशियन शेफर्ड, टोनजैक, सरप्लानिनैक, जापानी तोसा ऐंड अकिता, मास्टिफ्स, रॉटलवियर, टेरियर, रोडेशियन रिजबैक, वोल्फ डॉग्स, कनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, केन कार्सो शामिल हैं।

सीएए के खिलाफ हैं कमल हसन सहित दक्षिण के कई अभिनेता

नई दिल्ली। दक्षिण फिल्मों सहित हिंदी फिल्मों अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके कमल हसन सीएए का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन सीएए लागू किया गया है उसे वे काला दिन मानते हैं। कमल हासन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'भारत के लिए एक काला दिन। धर्म–आधारित नागरिकता परीक्षण गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक नींव के विपरीत है, और मैं इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा।' यानी अब वे इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज आगे भी उठाएंगे और उन्होंने इसके विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प भी ले लिया है। इससे पहले दूसरे तमिल स्टार थलापति विजय ने भी इस बिल के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। विजय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान में कहा, 'ऐसे माहौल में जहां देश के सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) जैसे किसी भी कानून को लागू करना स्वीकार्य नहीं है।' इसके साथ ही थलापति विजय ने अपनी राज्य सरकार से अपील की है कि वो इसे किसी भी कीमत पर तमिलनाडु में लागू ना करें। एक्टर के इस पोस्ट कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। विजय अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हैं और वे कुछ एक प्रोजेक्ट के बाद फिल्मों से संन्यान ले लेंगे। बात अगर विजय के वर्कफ्रंट की करें तो पिछले साल उनकी फिल्म लियो आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब वे अपनी अगली फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' में धमाल मचाने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिससे जाहिर होता है कि ये भी एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में सीएए लागू कर दिया है। जहां तमाम लोग इस बिल के पास होने का जश्न मना रहे हैं तो वहीं कई इसके खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां खासकर इस फिल्म को सिरे से नकार रही हैं। वहीं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी इस बिल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो फिल्मों के साथ– साथ राजनीति में भी सक्रीय हैं।

काला जठेड़ी को गृह प्रवेश के लिए नहीं मिली पैरोल...पत्नी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में

नई दिल्ली। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की दिल्ली में शादी हुई है। इसके लिए काला जठेड़ी को छह घंटे की परोल मिली थी। हालांकि डॉन को गृह प्रवेश के लिए भी बुधवार को तीन घंटों की परोल दी गई थी, इस बात में वापस ले लिया गया है। इस लेकर अब डॉन की पत्नी अनुराधा चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। अनुराधा ने कहा कि मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में अर्जी लगा रही हूं। गृह प्रवेश केबाद ही संदीप के घर में घुसा जाएगा। कोर्ट ने बुधवार को सोनीपत के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश के लिए 3 घंटे की परोल दी गई थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून–व्यवस्था का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे। अनुराधा ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करेंगी। इस लेकर अर्जी दाखिल की जाएगी। उधर, लोअर कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। यह देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है?

105 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया, कांग्रेस को दो दिन में दो झटके

–दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से बकाया 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखा है। मंगलवार को भी हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा था। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाकर पूछा था कि क्या तीन साल तक सो रहे थे। कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा उसकी अप्लीकेशन अस्वीकार करने को लेकर कोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को 105 करोड़ से ज्यादा के बकाए टैक्स की वसूली को लेकर नोटिस जारी किया था। मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि क्या इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई खामी नहीं नजर आती है। कोर्ट ने गौर किया कि कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2021 में शुरू हुई थी। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाकर पूछा कि क्या अभी तक सो रहे थे। बेंच ने कहा था कि इस मामले को बहुत ही गलत ढंग से हैंडल किया गया है।

दिल्ली में धड़ल्लें से बेंची जा रही नकली कैंसर की दवा

–दिल्ली पुलिस ने किया एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें दो आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल नौ ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की हैं। इसमें सात दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की जबकि दो भारतीय ब्रांड की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी कैंसर अस्पताल में मरीजों को कीमोथैरेपी में इस्तेमाल में लाने वाले इंजेक्शंस की खाली शीशी जुटाते थे, फिर उन शीशियों में एंटी फंगल दवा भरकर बेचते थे। आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खासकर हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वे अपना शिकार बनाते थे। जिन सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। इसमें नीरज गुरुग्राम निवासी है, जबकि बाकी के छह दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली है कि दिल्ली में एक गैंग सक्रिय है, जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई। टीम को जांच में चार अलग–अलग जगह की जानकारी मिली, जहां से नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगह पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका नहीं मिले। टीम ने डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में छापेमारी की, जो इस रैकेट का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। पुलिस के मुताबिक यहां पर विफल जैन कैंसर की नकली दवाइयां को बनाता था। विफल ही इस पूरे गैंग का सरगना भी था। विफल ने डीएलएफ ग्रीन्स में दो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स किराए पर ले रखे थे। यहां पर ये कैंसर की दवा की खाली शीशियों में नकली दवाई भर देता जबकि इसका साथी सूरज इन दोबारा भरी गई शीशियों को अच्छे तरीके से पैक करता था ताकि किसी को शक ना हो।

आम चुनाव में मोदी की गारंटी को टक्कर देने आ गई कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी

–गरीब महिला को एक लाख रुपये और नौकरी का वादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटे पार्टी आलाकमान ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। नारी न्याय गारंटी की घोषणा कर पार्टी सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी देश की आधी आबादी के लिए नया एजेंडा सेट करेगी।

खरगे ने कहा, कांग्रेस नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है। उन्होंने गारंटियों के नाम भी गिनाए। पहली गारंटी-महालक्ष्मी गारंटी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी का ऐलान भी किया गया। खरगे ने कहा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर गरीब परिवार की एक-एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की मदद मिलेगी। दूसरी घोषणा-आधी आबादी पूरा हक के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पदों पर महिलाओं का अधिकार होगा।

तीसरी गारंटी- शक्ति का सम्मान के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र का योगदान दोगुना होगा। कांग्रेस की चौथी गारंटी- अधिकार मैत्री है। कांग्रेस इसके तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगी। हर पंचायत में एक पैरालीगल नियुक्त किया जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा के अलावा महिलाओं की मदद भी की जाएगी।

कांग्रेस ने जिस पांचवीं गारंटी का जिक्र किया है, इसमें शिक्षा पर फोकस करने का वादा किया है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी के तहत भारत सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक छात्रावास बनाएगी। देश भर में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी करने का वादा भी किया है।

गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस प्रमुख खरगे ने आदिवासियों से जुड़े छह संकल्पों की घोषणा की थी। खरगे ने कहा था कि उनकी पार्टी जल-जंगल और जमीन को बचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के छह संकल्पों का भी जिक्र किया।

उद्धव ठाकरे का तंज बोले– कश्मीरी पंडितों की बगैर वापसी के अधूरा है सीएए

मुंबई। सीएए लागू होते ही कई जगह से विरोध के स्वर उठे हैं तो वहीं विपक्षी नेता भी सरकार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो जाती है तब तक सीएए लागू करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मंगलवार को कहा, देश में नया कानून सीएए लाया गया है। जो हिंदू, सिख, पारसी और जैन देश के बाहर डरे हुए हैं, उन्हें हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें जरूर लाया जाए, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है।ठाकरे ने आगे कहा, जब मैं सीएम था, तो भाजपा देश में सीएए और एनआरसी का भूत लेकर आई थी। उस समय लोगों के मन में डर पैदा हो गया, खासकर असम के लोगों के मन में। इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं हैं। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, धर्मों के बीच भेदभाव पैदा कर झगड़े और दंगे कराना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में एक तरफ बीजेपी है जो धर्मों के बीच नफरत पैदा कर रही है और दूसरी तरफ देशभक्त इंडिया गठबंधन है। यह चुनाव देशभक्त बनाम नफरत करने वालों के बीच होने जा रहा है। अगर आप विदेशों से हिंदुओं को हमारे यहां लाना चाहते हैं तो पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ और फिर सीएए लाओ।इस मुद्दे पर एनसीपी ने भी सरकार की आलोचना की है। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, अगले हफ्ते जो कुछ भी होने वाला है, जाहिर तौर पर उसका संबंध लोकसभा चुनाव से होगा। उन्होंने अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया? देश जानना चाहता है कि चुनावी बॉन्ड और पेटीएम में क्या हुआ। सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन है?

नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने के लिए गैर-लाभकारी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। फरवरी में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय चुनाव पैनल में दो रिक्तियों के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, पांडे के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद के लिए चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की इस सप्ताह बैठक होने की संभावना है।

नए कानून के तहत चयन पैनल में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता इसके सदस्य हैं। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका के जवाब में निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 में सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया, इस कदम को आलोचक देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निगरानीकर्ता को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयास के रूप में देखते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद से कुछ दिन पहले, अरुण गोयल ने पिछले शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया, यह मोदी सरकार के तहत किसी चुनाव आयुक्त द्वारा दिया गया दूसरा इस्तीफा है। अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लिए गए विभिन्न आदर्श आचार संहिता उल्लंघन निर्णयों पर असहमति जताई थी।

हाईकोर्ट का मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक से इनकार, राज्य को हलफनामा देने का निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के हालिया मराठा आरक्षण अधिनियम पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अंतिम सुनवाई और उनकी याचिकाओं के निपटारे तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों में संवैधानिकता का एक सिद्धांत है और इसलिए सभी तर्कों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि हम राज्य को अंतरिम राहत पर जवाब देने के लिए कुछ समय देना चाहते हैं। यह निर्णय एक साधारण प्रशासनिक आदेश नहीं है। यह एक कानून है। इसलिए हमें कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते समय निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। अनुमानित संवैधानिकता का भी एक सिद्धांत है। हमें सभी तर्कों को उचित महत्व देना होगा। पीठ ने कहा कि मराठों को आरक्षण देने का महाराष्ट्र सरकार का कदम एक कानून में निहित है न कि किसी प्रशासनिक आदेश में और राज्य को याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय चाहिए। पीठ ने राज्य सरकार को मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में अलग से 10 प्रतिशत कोटा देने वाले हाल ही में लागू कानून के कार्यान्वयन पर अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर हम 10 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।

सीएए पर झूठ फैलाना बंद करें विरोधी दल... किसी की नागरिकता या नौकरी नहीं जाएगी

–पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल और ममता की आलोचना की

नई दिल्ली (एजेंसी)। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू करने को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाओं के बीच बीजेपी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे इस कानून के बारे में झूठ फैलाकर सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना कर कहा कि यह कानून किसी भारतीय की नागरिकता या फिर नौकरी नहीं छीनता है।

केजरीवाल के दावे के संदर्भ में कि केंद्र की भाजपा सरकार भारतीयों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों को देना चाहती है, भाजपा नेता प्रसाद ने कहा कि आप नेता ने बहुत अजीब बयान दिया है। यह कानून उन अल्पसंख्यकों के लिए है जिन्हें तीन देशों में उनके धार्मिक विश्वास के कारण सताया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत में कठिन जीवन जी रहे हैं और क्या उन्हें नागरिकता देने में देश नैतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएए नागरिकता देने के लिए है और यह किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दल यह दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वे रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़े होंगे। उन्होंने कहा, जो लोग सीएए के नाम पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे इसके बारे में झूठ फैलाना बंद करें। प्रसाद ने दावा किया कि बनर्जी की जमीन खिसक रही है, इसकारण वे सीएए के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से अपील की कि वे नफरत फैलाना बंद करें। उन्होंने दावा किया कि आलोचकों के पास कानून के खिलाफ कोई तर्क नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधकर कहा कि इन सभी का राजनीतिक आधार डूब रहा है। प्रसाद ने कहा कि भारत ने एक देश के तौर पर अपनी सभ्यतागत विरासत और संवैधानिक दायित्वों के कारण तीनों देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत संरक्षण प्रदान किया है।

राज्यपाल ने सीएम ममता को दिया सुझाव कहा– बोलने से पहले सीएए का अध्ययन कर लें

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को सलाह दी कि वह इस पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के ब?योरे का अध्ययन कर लें और समझ भी लें। मुख्यमंत्री द्वारा सीएए की कानूनी पवित्रता पर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है, जिसका उद्देश्य देश को विभाजित करना नहीं, बल्कि भारत को एकजुट करना है।

राज्यपाल ने कहा, मैं अपनी संवैधानिक सहयोगी, मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे पहले अधिनियम के विवरण का अध्ययन करें और समझें, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करें। उन्होंने कहा कि सीएए दिसंबर 2019 में संसद के पटल पर पारित किया गया था और सोमवार को इसे कानूनी प्रावधानों के अनुसार लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। राज्यपाल ने कहा, यह कानूनी वास्तविकताओं के साथ-साथ सुशासन को भी दर्शाता है। मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने सीएए पोर्टल पर नामांकन के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आवेदक अंततः अपना सब कुछ खो सकते हैं।मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी, जब पोर्टल पर आवेदन करेंगे, तो आप वास्तविक नागरिक से अवैध प्रवासी बन जाएंगे और एक बार जब आप अवैध प्रवासी बन गए, तो आपकी संपत्ति और पेशे का क्या होगा? आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, इसलिए आवेदन करने से पहले दो बार सोचें। हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करने के लिए अनावश्यक रूप से इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में बदला मौसम, गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, 14 मार्च तक गीला मौसम रहने की संभावना

श्रीनगर (एजेंसी)। प्रसिद्ध स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है क्योंकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को प्रभावित किया है। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और अन्य इलाकों में आज दोपहर तक बीच-बीच में धूप देखने को मिली, जिसके बाद गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे कई स्थानों पर पारा नीचे आ गया। हालांकि, आज शाम श्रीनगर और अन्य इलाकों में बारिश हुई।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आज बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे जम्मू-कश्मीर प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में एक और चक्रवात जम्मू-कश्मीर को प्रभावित कर रहा है।

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि कल 12 मार्च को आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे जबकि 13 मार्च को तेज हवाओं के साथ गरज-चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 14 मार्च को मौसम आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बहरहाल, उन्होंने बताया कि 15 मार्च से 20 मार्च तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा।

मौसम विज्ञानियों ने पूर्वानुमान के मद्देनजर एक सलाह भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में जनता को हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों और ढलान वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी जाती है, और उनसे हिमस्खलन की चेतावनियों और सलाह का पालन करने की अपील की जाती है। इसके अलावा, किसानों को कृषि कार्यों को फिर से शुरू करने की सलाह दी गई है।

हालिया बर्फबारी के बाद, जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में दूधपथरी 12 मार्च को एक आश्चर्यजनक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया, जिसने प्रकृति प्रेमियों और टट्टू सवारों को समान रूप से आकर्षित किया। सुरम्य परिदृश्य ने आगंतुकों को बर्फ से ढके इलाके का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। बर्फबारी के बाद टट्टू की सवारी गतिविधियों की मांग बढ़ गई क्योंकि पर्यटक दूधपथरी की शांत सुंदरता में डूबने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय टट्टू संचालकों ने इस उत्साहजनक गतिविधि का अनुभव करने के लिए आगंतुकों की आमद को पूरा करते हुए व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।

एएनआई से बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा, %यहां चार गांव हैं और हमारी आय पर्यटन पर निर्भर है। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं तो हमारी आय बढ़ती है। उन्हें सवारी पर छूट भी मिलती है। एक अन्य स्थानीय ने कहा, ÷बर्फबारी के बाद हमारी आय बढ़ गई है। हम पर्यटकों को दूधपथरी ले जाते हैं और उन्हें पांच से छह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिखाते हैं।÷ अनुभव के बारे में बात करते हुए एक पर्यटक ने कहा, ÷घुड़सवारी का अनुभव अद्भुत था। कार से यात्रा करने के लिए यह बहुत कठिन इलाका है; इसलिए घोड़े सबसे अच्छे विकल्प हैं। यह एक अद्भुत एहसास है।

400 पार के नारे पर खटटर बन रहे थे रोड़ा... भाजपा ने हटकर सोशल इंजीनियरिंग पेश की

–जजपा को अलविदा कहकर जाट वोट को तोड़ दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में पहले हरियाणा की सियासत में हुए बड़े बदलाव ने सभी को हैरान किया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाने और जजपा के साथ गठबंधन तोड़कर अपना रास्ता आसान किया है। भाजपा के विश्वस्त सूत्रों की मानें, तब हरियाणा की मौजूदा परिस्थितियों में पांच लोकसभा सीटों पर पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के जुड़े सूत्रों की माने तब प्रधानमंत्री मोदी का नारा, अबकी बार 400 पार की राह में मुख्यमंत्री खट्टर को लेकर विरोधी लहर एक बड़ी बाधा बन रही थी। नतीजा, भाजपा को पिछड़े समुदाय के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर नई सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कई एजेंसियों के द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार कराई थी। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन को लेकर नतीजे वे उत्साहवर्धक नहीं थे। खासकर से रोहतक, हिसार और सोनीपत की लोकसभा सीट पर भाजपा की राह मुश्किल थी। इसके अलावा भिवानी-महेंद्रगढ़ और सिरसा लोकसभा क्षेत्र, ये दोनों सीटें भी पार्टी के लिए आसान नहीं बताई जा रही। जो रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें खटटर ने जिस सख्ती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे प्रदेश में कुछ समुदाय असहज महसूस कर रहे थे। इसमें जाट समुदाय पहले नंबर पर था। लोगों की यह शिकायत रही कि खट्टर उनके साथ, वैसे नहीं मिलते थे, जैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मिलते रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि खट्टर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में योजनाओं को त्वरित गति से लागू किया गया। प्रदेश में कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। खट्टर के अलावा कैबिनेट मंत्री, विधायक और आम जन भी यह बात स्वीकार करते रहे हैं कि प्रदेश में नौकरी देने में पूर्ण ईमानदारी बरती गई है। हरियाणा की सियासत पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सैनी बताते हैं, इस बात पर बहुत से लोग सहमत हैं कि खट्टर के कार्यकाल के दौरान खर्ची और पर्ची का दौर बंद हो गया था। नियुक्तियों में सभी वर्गों के युवाओं का प्रतिनिधित्व था। खट्टर के कार्यकाल में शिक्षकों के तबादले एक क्लिक पर होने लगे। शिक्षकों को किसी से अप्रोच नहीं करानी पड़ती। वे घर बैठे बिठाए ही अपने जिले व स्कूल का चयन करते हैं। नियमों के अनुसार, उन्हें नई पोस्टिंग मिल जाती है।

हालांकि इसके बीच मुख्यमंत्री को लेकर यह बात कही गई कि उनकी आम जनता से दूरी बढ़ती जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव आते-आते वह दूरी एंटी इनकम्बेंसी में बदल गई। भाजपा नेतृत्व ने इस बात को समझा और दो बड़े निर्णय ले लिए। पहला, जजपा से गठबंधन तोड़ा और दूसरा, खट्टर की जगह पर नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, प्रदेश की राजनीति जाट और गैर जाट वोटरों के बीच घूमती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर भी गैर जाट समुदाय से आते हैं और वर्तमान सीएम भी इसी समुदाय से आते हैं। फर्क इतना है कि खट्टर, जिस पंजाबी समुदाय से हैं, वह सामान्य वर्ग में आता है। नायब सैनी, पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहां पर भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को नए रूप में पेश किया है।

प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 25 फीसदी है। पंजाबी समुदाय आठ फीसदी, ब्राह्मण साढ़े सात फीसदी, मुस्लिम साढ़े तीन फीसदी और गुर्जर समुदाय भी तीन फीसदी से अधिक हैं। इनके अलावा वैश्य समुदाय की आबादी भी लगभग पांच फीसदी है। यादव

समुदाय भी पांच फीसदी से अधिक है। सैनी समुदाय करीब तीन फीसदी है। हरियाणा में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत 20.2 से अधिक है। भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन तोड़कर जाट वोटरों को विभाजित करने का प्रयास किया है। अगर भाजपा और जजपा का गठबंधन जारी रहता, तब लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय का बड़ा हिस्सा, कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था। इससे चुनावी समीकरण बिगड़ने की आशंका थी। इसकारण भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दहलीज पर जजपा से नाता तोड़ लिया।